RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ 'सब्र' की होती है...।

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

वर्ष-07, अंक - 22 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 20 फरवरी 2025 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित खवासा

शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित
DR/JHB/147421
विश्वास का संगम, समृद्धि का रास्ता
MP-2025

भव्य शुभारंभ

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

सहकार से समृद्धि

बिना सहकार - नही उद्धार

आपसी विश्वास और नेकी आधारित व्यवसाय ही हमे समृद्धि व उन्नयन के पथ पर अग्रसर करता है। यही भरोसा लेकर सहकारिता की पीठिका पर हम आप से जुड़ रहे है। आप के साथ मिलकर तरक्की के साझा सपने को साकार करने के उद्देश्य से हमने सहकारिता के क्षेत्र में कदम रखा है। आप के अटुट संबंध से ही हम शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित खवासा का शुभारंभ सम्माननीय अतिथि सहकारिता के इंदौर संभागीय संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहकारिता से जुडे वरिष्ठगण, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिको की उपस्थिति के साथ कर रहे है।

जनमानस की गरिमामय उपस्थिति ही इस शुभारंभ समारोह की भव्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता उत्सव वर्ष 2025 में वृद्धि करेगी।

शुभारंभ का शुभपल

21 फरवरी 2025 शुक्रवार प्रातः 11 बजे

स्थान – श्री सतगुरु पैलेस, बाजना मार्ग, रोग्या देवी मंदिर के पास खवासा जिला झाबुआ (म.प्र.)

विनीत :- संजय भटेवरा - अध्यक्ष शगुन शाख सहकारी संस्था मर्यादित एवं संस्था परिवार
खवासा, जिला झाबुआ (म. प्र.) मो.न. 9993840341

अकर्मण्यता की और ग्राम पंचायत खवासा

फरवरी माह से ही जल संकट प्रारंभ

माही की गूंज, खवासा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल किले के 2030 तक हर घर नल के माध्यम से पेयजल देने की योजना का ऐलान कर रहे हैं। वही मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की थांदला जनपद का सबसे बड़ा कस्बा ग्राम खवासा में नल जल योजना होने के बावजूद फरवरी माह से ही जल संकट का दुख सहने के लिए मजबूर है।

प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन यहां डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक (विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर) एक ही पार्टी के नेता होने के बावजूद इस तरह की मूलभूत सुविधा के लिए भी आम जनता मोहताज है।

सरपंच की कार्यप्रणाली विवादास्पद

चुनाव के समय सभी नेता, आम जनता के सारे दुख दर्द मिटाने का वादा करते हैं। वहीं चुनाव के पश्चात निजी हितों के लिए आपसी मनमुटाव कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत खवासा का है। यहां सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद कई वर्षों से सरपंच पद के लिए संघर्षरत भाजपा व संघ से जुड़े हुए शंकर सिंह खराड़ी ने अपनी मां जो की सेवानिवृत्ति शासकीय कर्मचारी है, को सरपंच का चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की। तब लोगों को लगा था कि, सहज, सरल व विनम्र स्वभाव के धनी शंकर सिंह खराड़ी गांव के लिए अच्छी सोच के साथ ग्राम पंचायत के विकास के लिए कुछ कार्य करेंगे। लेकिन जल्दी ही ग्रामवासियों का यह भ्रम टूट गया। जब पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव के विकास के बजाय अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए आपसी मनमुटाव करने लग गए। तो नतीजा यह हुआ कि, वरिष्ठ नेताओ ने ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों से दूरी बना ली, यहां तक कि गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी अधिकांश पंच सहित वरिष्ठ नेता नदारत रहने लग गए। इस संवाधीनता का सीधा असर ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। ग्राम पंचायत की ओर से कोई नया या बड़ा कार्य शुरू नहीं किया जा पा रहा है। यहां तक कि, रूटीन के कार्यों में भी मनमुटाव का असर आम जनता को स्पष्ट नजर आ रहा है। वर्षों से व्याप्त जल संकट के स्थाई समाधान के लिए चुनावी समय में बड़ी-बड़ी बातें की जाती है लेकिन चुनाव के पश्चात मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चार-पांच वर्ष पूर्व नवनिर्मित दुकानों की नीलामी अब तक नहीं हो पाई है, दो बार प्रयास किए गए और दोनों ही बार ऐंड वक्त पर नीलामी निरस्त करने से आम लोगों में ग्राम पंचायत के प्रति असंतोष नजर आ रहा है। वही पुराने पंचायत भवन और कांजी हाउस को तोड़ दिया गया है। लेकिन उस पर प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स के निर्माण संबंधी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। जिसमें मेन रोड की उस भूमि पर अतिक्रमण पसरता जा रहा है। पशु हाट व स्थानीय बाजारों के नीलामी से पंचायत को अच्छी आय प्राप्त होती है। उसका मात्र ठेका देकर पंचायत निश्चिंत हो गई है। कोई अन्य व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत नहीं जुटा पा रही है। जल संकट का समाधान, ग्राम की आंतरिक जर्जर सड़के, स्ट्रीट लाइट जैसे अन्य कार्य जो पंचायत द्वारा किए जाने चाहिए, वह कार्य भी पंचायत के नुमाइंदे नहीं कर पा रहे हैं। फरवरी माह से ही व्याप्त जल संकट अप्रैल, मई और जून में और अधिक गहरा सकता है। ऐसे में ग्रामवासियों को चिंता सता रही है कि, फरवरी माह में ही आठ दिन में नल आ रहे हैं तो मई, जून में क्या हाल होगा...?

संवादहीनता खत्म हो

ग्राम पंचायत के नुमाइंदो में व्याप्त आपसी अनबन के असर को देखते हुए ग्रामवासियों का कहना है कि, लोगों ने पंचायत के नुमाइंदो को ग्राम पंचायत में ग्राम के विकास के लिए भेजा है और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को चाहिए कि, वह ग्राम के हित में अपने आपसी मनमुटाव को त्याग कर निजी हितों को तिलांजलि देकर कार्य करें। साथ ही ग्राम के वरिष्ठ नेताओं से भी मार्गदर्शन लेकर कार्य करें। जिनसे उनका चुना जाना सार्थक साबित हो सके। क्योंकि लोकतंत्र में आम जनता ही सब कुछ है वह अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर भी बिठा सकती है।

स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में: भेरूगढ़ हाई स्कूल के बच्चे स्कूल से रेलवे पटरी क्रास कर जा रहे पानी भरने

बच्चो का वीडियो वायरल लेकिन प्रशासन अब भी सोया हुआ

माही की गूंज, खवासा।

एक तरफ प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए नींत नए प्रयास करने के साथ ही बच्चों को हर वह सुविधा मुहैया करवाने के दावे कर रही है, जिससे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे अधिक से अधिक पड़े। यही नहीं छात्रवृत्ति से लेकर साइकिल वितरण के कार्यक्रम व बच्चों को मध्यान भोजन देने की सुविधा भी शासन ने कर रखी है। तो पानी समस्या से निजात पाने के लिए स्कूलों में जल जीवन जल मिशन के तहत हैंड वॉश यूनिट के साथ ही बच्चों को पीने के लिए पानी की टंकी आदि लगाई गई थी। लेकिन कई स्कूलों में आज भी बच्चों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी व मॉनेटिंग करने वाले विभागीय अधिकारी इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार खवासा कन्या शाला संकुल के अंतर्गत आने वाली भैरूगढ़ हाई स्कूल का सामने आया है। सोमवार को बच्चे स्कूल गए और हमेशा की तरह रेलवे ट्रैक पार करते हुए हाथ मे केन लिए पानी भरने के लिए पहुंचते हैं। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि, बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है यहां की संस्था प्रभारी भी बच्चो के जीवन को खतरे में डाल रही है, लेकिन उसे उसका तनिक भी अहसास नही है। जिसके कारण ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। माही की गूंज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार व शासन के ऊपर यह करारा तमाचा है कि, आज भी ग्रामीण अंचलों में विद्यार्थियों से इस तरह से कार्य करवाया जा रहा है और उनके जीवन को भी खतरे में डाला जा रहा है। यह देखकर स्पष्ट होता है कि, प्रशासन स्कूली बच्चो के भविष्य को खतरे में डालकर कुंभकर्णीय निंद में सोया है, इसी लिए इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुरी तरह से अंजान बना हुआ है। लेकिन समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है यह देखना दिलचस्प रहेगा, या फिर आगे भी इसी तरह उनके बच्चो के जीवन को खतरे में डाला जाएगा, यह भी आगे ही पता चलेगा।

पानी भरने के नाम पर इस तरह से रेलवे ट्रैक पार कर बच्चे अपने जीवन को डाल रहे खतरे में, और कुंभकर्णीय निंद में सोया है प्रशासन।

अ से असाक्षर ही रह गए नवसाक्षर

नवसाक्षरों को बिना परीक्षा लिए कागज़ी खाना पूर्ति कर, कर दिया साक्षर

माही की गूंज, खवासा।

पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण योजना जिसमें असाक्षरों को साक्षर बनाने कि कवायद पूरे प्रदेश में चल रही थी और ऊपरी अधिकारी से लेकर अंतिम पंक्ति के कर्मचारी इस राष्ट्रीय महायज्ञ में आहुति देकर असाक्षरता के कलंक को मिटाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पूरे प्रदेश भर में इस योजना का अमली जामा पहनाने के बाद रविवार 16 फरवरी को शहर से लेकर फलिये तक के स्कूल पर इसके परिणाम के लिए परीक्षा आयोजित की गई। कई जगह तो इस आयोजन को उत्सव का रूप देकर इस महती कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर राष्ट्र की प्रगति में अधिकारियों और शिक्षक कर्मचारीयो ने सहभागिता कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया और अधिकारीयो ने इस आयोजन की सतत् मॉनिटरिंग की। यहां तक कि लापरवाही बरतने वालो पर भी निलंबन कर कार्यवाही की गई। अगर पड़ोसी जिले अलीराजपुर की ही बात करें तो वहां कई लापरवाह जनशिक्षकों और शिक्षकों पर गाज गिरी, वहां लगभग दस हजार असाक्षरों को इस परीक्षा में शामिल करने हेतु जनशिक्षकों को नामांकन करने का लक्ष्य दिया था। लापरवाही बरत रहे लगभग छः जनशिक्षकों को निलंबन किया गया।

देवगढ़ के भमरिया स्कूल में नही हो पाई परीक्षा।

वहीं अगर हम आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले की बात करें तो यहां बड़ी गम्भीर लापरवाही बरतने का उदाहरण सामने आया। भामल संकुल के अंतर्गत आने वाली देवगढ़ पंचायत के भमरिया फलिये में जहाँ नियमित तीन शिक्षक है और रविवार को परीक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालय भमरिया में रविवार 16 जनवरी को तो इस प्रकार के आयोजन की जिम्मेदार शिक्षकों ने ना तो फलिये के लोगों को जानकारी दी और न ही परीक्षा केंद्र के ताले खुले। हमारे प्रतिनिधि ने जब सत्यता की जानकारी के लिए भमरिया फलिये के सेंटर प्राथमिक विद्यालय भमरिया पहुंच कर देखा तो, विद्यालय में ताले जड़े मिले।

स्कूल से लगे खेत में काम कर रही गाँव की महिला से इस आयोजन सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि, आज तो रविवार हैं छुट्टी हैं आज कोई सर नहीं आए हैं रोजाना सर लोग स्कूल आते हैं या नहीं ...? तो महिला ने बताया यहां तीन शिक्षक हैं और 11 बजे आते हैं और तीन बजे छुट्टी कर चले जाते हैं।

जब हमारे प्रतिनिधि ने उक्त विद्यालय के प्रभारी शिक्षक मुकेश पाटीदार से जानकारी ली तो उन्होंने बताया, परीक्षा तो हुई थी, हमारा सेंटर देवगढ़ में था 4 पुरुष और 6 महिलाएं थी। मुझे नाम पता मालूम नहीं है क्योंकि मैं शादी में चला गया था, कहकर अपने जवाब से इति श्री कर ली। वही 3 बजे स्कूल के बंद होने के जवाब पर शिक्षक ने बताया कि, हमारे पास में मेघनगर का एरिया भी पड़ता है जहां से बच्चे आते हैं तो उनको जल्दी छुट्टी करनी पड़ती है। इसलिए कभी-कभी बच्चों की छुट्टी जल्दी कर देते हैं वही हम तो नियमित आ रहे हैं, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है और परीक्षा तो हुई है।

साक्षरता अभियान के प्रभारी सेतु कटारा ने बताया कि, देवगढ़ में परीक्षा हुई थी अब कौन झूठ और कौन सही या ग्रामीण झूठ या सही यह तो जांच का विषय है। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रतिनिधि ने पूछा कि, उन चार पुरुष व 6 महिलाओं के नाम बताओ तो प्रभारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि, मैं थोड़ी देर में नाम पता बताता हूं लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। इसमे अगर अधिकारी जांच करें और धरातल पर जिनकी परीक्षाएं उनसे पूछे तो लापरवाही उजागर हो सकती है।

मामले में भामल संकुल के प्रभारी प्राचार्य मकनसिंग निनामा ने बताया कि, मैं मामले को दिखवाता हु परीक्षा क्यों नहीं हुई है उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

संत शिरोमणि महाराज की जयंती मनाई

माही की गूंज, पेटलावद।

झाबुआ जिले के विभिन्न डांडो में बंजारा समाज द्वारा संत श्री शिरोमणी सेवालाल जी महाराज की 286वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणजन और महिलाएं शामिल हुए। महिलाएं नृत्य करते हुए और गरबा खेलते हुए शोभायात्रा में भाग ले रही थीं, वहीं पुरुष एक जैसे वेशभूषा में दिखे।

शोभायात्रा का दृश्य बहुत ही आकर्षक था और क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बोधिक प्रमुख शुभम पंवार, जिला सह कार्यवाह संतोष निनामा, प्रवासी समुदाय विभाग के सह संयोजक पर्वतनाथ देवड़ा, जिला संयोजक कैलाशनाथ चौहान और जिला सह संयोजक भारत राठौड़ ने बतौर अतिथि शिरकत की।

अतिथियों ने समाजजनों को इस विशेष दिन पर बधाई दी और समाज के मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया।

इस अवसर पर पिपलीपाडा से कैलाश नायक, भवरसिंह मनावत, टांडालाला नायक, हुकमसिंह पंवार, गोवर्धन मनावत, प्रेमसिंह मनावत, धनसिंह मनावत, गोढानिया खुर्द से भारत सिंह मानवत, संजय पंवार सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

इस आयोजन ने बंजारा समाज के एकजुटता और आस्था को और अधिक प्रगाढ़ किया, और सभी ने मिलकर संत शिरोमणी सेवालाल जी महाराज की जयंती को बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया।

'हनुमानजी' कहलाने लगे ललित, अजीब बीमारी से दुनियाभर में हुए फेसम

माही की गूंज, रतलाम।

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के छोटे से गांव नांदलेटा के रहने वाले हैं ललित पाटीदार, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, ललिता का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

दरअसल, ललित एक अजीब बीमारी से पीड़ित है. उनके चेहरे से लेकर शरीर पर लंबे-लंबे घने बाल हैं। अक्सर लोग ललित के देखकर डर जाते थे। बच्चे को उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। बचपन में ललित को काफी चिढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं लोग उन्हें बाल हनुमान कहने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इतनी परेशानियों के बाद भी ललित ने हार नहीं मानी।

सोशल मीडिया के जरिए ललित ने खुद को आगे बढ़ाया। फिर धीरे-धीरे सबकुछ बदल गया। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो अब उनके दोस्त बनने लगे। ललित का नाम अब सम्मान के साथ लिया जाने लगा। ललित से जो लोग नफरत करते थे, अब वहीं उससे हमदर्द बन गए। फिर ललित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

क्या है वेयरवोल्फ सिंड्रोम

नंदलेटा गांव के रहने वाले ललित पाटीदार वेयरवोल्फ सिंड्रोम से पीड़ित हैं। चेहरे पर 201.72 सेमी बाल है। अब 13 फरवरी को ईटली के मिलान शहर में उन्हें अवॉर्ड भी दिया गया है। शरीर पर बाल होना तो आम बात है। मगर ललित के चेहरे से लेकर शरीर में लंबे-लंबे घने बात हैं। वेयरवोल्फ सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर में काफी बाल होते हैं।

इस बीमारी की वजह से ललित के चेहरे पर असामान्य तरीके से बाल उग गए हैं। उनका पूरा चेहरा बालों से ढक गया है मानों किसी फिल्म का किरदार हो। इस वजह से लोग उन्हें वूल्फ मैन कहकर भी बुलाने लग गए।

बीमारी ने बनाया दिया फेमस

इसी अजीब बीमारी ने ललित को पूरी दुनिया में फेसम बना दिया। अब उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उन्हें इटली के मिलान शहर में अवॉर्ड मिला है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने उनसे संपर्क किया था। फिर फरवरी में ललित अपने एक साथी के साथ इटली के मिलान शहर पहुंचे। इसके बाद वहां एक्सपर्ट्स की टीम ने ललित की जांच की। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक प्रोग्राम में उनके सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया।

ललित का कहना है कि जब मैं छोटा था, तो लोग मुझे हनुमान का अवतार मानते थे। लोग मुझसे डरते थे, लेकिन अब परिवार में मैं सामान्य रूप से रहता हूं। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करा सकता हूं।

सात साल से फरार दस हजार के इनामी को अकोदिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

माही की गूंज, अकोदिया।

अकोदिया थाना के अपराध क्रमांक 23/2018 धारा 429 भादवि 4, 5, 6, 9 गौवंश अधिनियम मे आरोपी सद्दाम पिता बाबू खां मंसूरी निवासी मेला ग्राऊण्ड पचोर हाल छापीहेडा जिला राजगढ का घटना दिनांक से ही फरार होकर विगत सात साल से फरार चल रहा था जिसका न्यायालय शुजालपुर के प्रकरण क्रमांक 1909/18 मे स्थाई वारंट जारी किया गया था।

पुलिस अधीक्षक यशपाल सिहं राजपूत के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया जाकर वारंटियों की गिरफ्तारी पर ईनाम की उद्घोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिहं राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल, एसडीओपी शुजालपुर निमेष देशमुख के निर्देशन मे थाना प्रभारी अरविन्द सिहं तोमर द्वारा वारंटी सद्दाम के संबंध मे जानकारी निकालने पर वारंटी के अलग-अलग पते प्राप्त हुये एंव जानकारी मिली की वारंटी सद्दाम उसके पते बदलता रहता है। थाना प्रभारी अरविन्द सिहं तोमर के द्वारा एक टीम गठीत कर टीम को वारंटी की तलाश मे लगाया गया। टीम के द्वारा वारंटी के अलग-अलग कई पतों पर जाकर लगातार अथक प्रयास किये एंव तकनीकी सहायता से दिनांक 17.02.25 को वारंटी सद्दाम को भैंसवा माता मेला जिला राजगढ से गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की है।

उक्त कार्य मे थाना प्रभारी उनि अरविन्द सिहं तोमर, सउनि खुशाल सिहं मुनिया, आरक्षक अंकित एंव सायबर सेल शाजापुर की भुमिका रही।

25 लाख का तालाब पर एक बूंद पानी नही

मस्टर जारी करने वाले इंजीनियर की भी लापरवाही, शासन के पैसों की हुई बंदरबांट

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत कई जगह 25 लाख से अधिक की लागत से तालाब बनाए गए। यह तालाब या तो वन विभाग के माध्यम से बनाए गए या आरईएस आदि विभाग द्वारा बनवाए जाते हैं। लेकिन इन तालाब के कार्य के नाम पर मात्र मामूली सा कार्य कर आधी राशि से भी कम का कार्य कर पुरी राशि की बंदरबाट हो जाती है। लेकिन इसे कोई देखने वाला नही है। फर्जी जॉब कार्ड भरकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। जिसकी वजह से धरातल पर तालाब में पानी ही नहीं मिलता है। जबकि सरकार द्वारा प्रति वर्ष मनरेगा योजना के तहत काफी बजट आवंटित किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर ही ग्रामीणों को रोजगार मिले लेकिन इन दिनों देखा जा सकता है कि, तालाब में मशीनो के माध्यम से कार्य किया जाता है। जिनकी जिम्मेदारी है, देख-रेख करने की वह भी कभी देखने की हिमाकत नही करते है। कभी आकर देख भी ले तो वह देखी भी महज ही औपचारिकता ही रहती है। जिससे साफ प्रतीत होता है, कि अधिकारी, एजेंसी व अघोषित ठेकेदार की मिली भगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है।

कुछ ऐसा ही मामला भामल ग्राम के रूपापाड़ा फलीए मे सामने आया, जो पिछले 2024 मे मार्च व अप्रेल मे तालाब बनाया गया जिसकी 24.99 लाख रुपए की लागत थी व निर्माण एजेंसी पेटलावद वन मण्डल क्षेत्र के अधिन आने वाली बिट भामल के रूपापडा मे तालाब बनाया गया। जबकि इस वर्ष बारिश भी अत्यंतधिक हुई उसके बाद भी एक बून्द तालब मे पानी नहीं है। वन विभाग पेटलावद के अधिकारियों ने भी इस और कोई देखना उचित नहीं समझा। जिसके कारण अघोषित ठेकेदार बैरागी ने मनमर्जी चलाई। जिस नियम कायदे से तालाब बनना चाहिए था उस नियम कायदे को ताक में रख घटिया निर्माण कार्य किया। जिसके कारण यह तालाब आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तालब का नाम चीरा माइनर टेंक वाइल्ड लाइफ भामल के नाम से बना है। निर्माण एजेंसी वन विभाग थी, तो मस्टर जारी करने में जनपद पंचायत के सब इंजीनियरों ने मामले में लीपा-पोती की। वही अघोषित ठेकेदारी अंबाराम बैरागी ने रस्म निभाकर तालाब में भ्रष्टाचार किया। अगर इसकी जांच हो तो भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाए। लेकिन यह जांच करें कौन...?

ग्रामीण हक़रु, वालू, गलिया, भुंडी, वालकी, जमुड़ी आदि ग्रामीणों ने बताया कि, जेसीबी से तालाब बनाए तथा मजदूर तो कम ही लगाए और जल्द ही तालाब का निर्माण कर दिया। हमने कभी भी अधिकारियों का यहां आते नहीं देखा। सिर्फ ठेकेदार ही खवासा से आता था और उसकी देख-रेख में काम होता था। मजदुर तो सिर्फ पानी पिलाने के लिए लगा रखे थे। पुरा निर्माण कार्य जेसीबी से ही हुआ।

रेंजर वन मंडल पेटलावद ओमप्रकाश बिरला का कहना है कि, आपके द्वारा मुझे बताया गया है तो मे खुद ही साइट पर जाकर देखूंगा और किस तरह से तालाब बना है उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित का होगा भव्य शुभारंभ...

माही की गूंज, झाबुआ/खवासा।

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से आम लोगों को बैंकिंग सुविधा में दैनिक बचत, बचत जमा, एफडी, आरडी एवं छोटे से छोटे व्यापारी को चाहे वह सड़क पर बैठकर या फिर हाथ ठेला गाड़ी में व्यापार करता है। ऐसे व्यापारियो को भी सुलभ सुविधा के साथ ऋण व्यापार में वृद्धि करने हेतु दिया जाएगा। साथ ही हमारी सरकारे, समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार की मनसा अनुसार इन समूह को व्यापार वृद्धि हेतु ऋण योजना सुविधा आदि योजना के साथ शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित का भव्य शुभारंभ 21 फरवरी को मान्य अतिथियों के कर कमलो से होगा।

शगुन साख सहकारी संस्था मर्यादित संस्था के अध्यक्ष संजय भटेवरा ने जानकारी देते हुए बताया कि, ÷बिन सहकार-नहीं उद्धार और सहकार से ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। तथा सहकारिता क्षेत्र में आपसी विश्वास व सम्मान मिलने का एक प्रतीक है, तो वह है सहकारिता। इसलिए अंशधारी यानी की संस्था के सदस्य-ग्राहकों को सम्मान, बैंकिंग व्यवस्था के दौरान मिले व संस्था के सभी सदस्य को बैंकिंग व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। तथा सरल व्यवस्था के साथ छोटे-छोटे व्यापारियों एवं समूह की महिलाओं को अपने व्यापार में वृद्धि हेतु ऋण मिले, और अपने व्यापार में वृद्धि कर क्षेत्र व जिले के विकास में भागीदार बने। के उद्देश्य के साथ उक्त संस्था का शुभारंभ 21 फरवरी को किया जा रहा है।

उक्त भव्य शुभारंभ में विशेष रूप से मंचासिन अतिथि के रूप में बीएल. मकवाना (संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक सहकारिता इंदौर संभाग), दिनेशचन्द्र भिड़े (उपायुक्त सहकारिता जिला झाबुआ), श्रीमती प्रिया चिराग भानपुरिया (सहकारी निरीक्षक सहकारिता जि. धार/म.प्र. शासन द्वारा नवनियुक्त सहायक संचालक - शिक्षा विभाग), शैलेष दुबे (पूर्व अध्यक्ष-नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ), प्रदीप त्रिपाठी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी- नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ), श्रीमती गंगा बाई खराड़ी (सरपंच ग्राम पंचायत खवासा), श्रीमती माया देवी प्रेमसिंह चौधरी (जनपद उपाध्यक्ष- जनपद पंचायत थांदला), हेमन्त चौपड़ा (वरिष्ठ पत्रकार-खवासा), श्रीमान शांतिलाल पाटीदार (पूर्व सीईओ), गोवर्धनलाल चौहान (अध्यक्ष - तेली समाज खवासा), रमेश बारिया (पूर्व सरपंच - ग्राम पंचायत खवासा) शिरकत करेंगे, जिनके हाथो से संस्था का शुभारंभ किया जाएगा।

उक्त भव्य शुभारंभ अवसर पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को उत्सव दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। उक्त आयोजन को भव्यता देने हेतु समस्त व्यापारी, महिला समूह, जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी गण, गणमान्य नागरिक आदि सभी से संस्था के अध्यक्ष व संस्था परिवार ने अपील की है कि, आप सभी अधिक से अधिक उक्त भव्य शुभारंभ अवसर पर एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव दिवस को मनाने हेतु 21 फरवरी को 11:00 बजे आयोजन में पधारे एवं आयोजन को भव्यता प्रदान करें।

वन विहार करते हुए ब्रज की होली मनाई

माही की गूंज, पेटलावद।

रसीया गित व भजनों के साथ भगवान कृष्ण को होली खेलने का निमंत्रण देते हुए वसंत उत्सव समारोह में ब्रज की होली का अद्भुत आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान भगवान राधा कृष्ण को वन विहार कराते हुए फाग उत्सव का उल्लासपूर्ण माहौल बना।

श्री जी पथ भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, कथा प्रवक्ता सुश्री वैष्णवी भट्ट के सानिध्य में नगर में पहला वसंत उत्सव समारोह मनाया गया। यह समारोह खोरिया हनुमान मंदिर के जंगल में हुआ, जहां भक्तों ने भगवान राधा कृष्ण के साथ वन विहार करते हुए फाग गीतों, रसिया और भजन-कीर्तन का आनंद लिया।

कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए और तीन घंटे तक चले इस उत्सव में महाआरती का आयोजन भी हुआ। भक्तों ने भगवान को फूलों और गुलाल से होली खेलाई, साथ ही उत्सव के रंगों में रंग कर आनंद लिया। इस आयोजन में भगवान राधा कृष्ण की छवि अत्यधिक मोहक और आकर्षक प्रतीत हो रही थी, जो भक्तों के दिलों को छू गई।

सुश्री वैष्णवी भट्ट के मार्गदर्शन में इस उत्सव को लेकर भक्तों में गहरी श्रद्धा और उल्लास देखने को मिला। नगरवासियों ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था और यह उनके लिए एक नई धार्मिक अनुभूति रही।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सुश्री वैष्णवी भट्ट ने नगर में राधा रसामृत कथा का पंच दिवसीय आयोजन और राधा कृष्ण विवाह उत्सव का सफल आयोजन किया था, जिसे भक्तों ने खूब सराहा।

इस वसंत उत्सव के आयोजन से नगर में ब्रज की होली का माहौल बना और भक्तों ने इस धार्मिक आयोजन का भरपूर आनंद लिया, जो उनकी आस्था को और भी मजबूत करता है।

श्री शिव परिवार त्रि-दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव

माही की गूंज, पारा।

पारा बोरी मार्ग स्थित प्राचीन श्री पृथ्वीराज महादेव मंदिर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।

19 फरवरी बुधवार को प्रातः 9 बजे से महोत्सोव की शुरूआत होकर, श्री राम मंदिर से शिव परिवार की शोभायात्रा आतिशबाजी के साथ ग्राम की प्रमुख गलियों से निकली। शोभायात्रा के दौरान ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा में तीन बगी बनाई गईं, पहली बगी में शिव परिवार, दूसरी बगी में 1008 श्री दयाराम दास जी और तीसरी बगी में श्री कानु जी महाराज विराजमान हुए। इस शोभायात्रा में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं एवं युवा वर्ग शामिल हुए, ग्राम के हर चौराहे पर गरबा नृत्य किया। कलश यात्रा पुनः पृथ्वीराज महादेव मंदिर पहुंची, जहां शिव भक्तों ने श्री रामचरित मानस के अखंड पारायण का आयोजन प्रारंभ किया। इसके साथ ही पंचांग कर्म, अग्नि स्थापना, जलाधिवास, फला-पत्र और पुष्पाधिवास जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी सम्पन्न हुए।

आज श्री रामचरित मानस अखंड पारायण की पूर्णाहुति के बाद देवी-देवताओं का पूजन, यज्ञ, अन्नाधिवास, महास्नान और महाअभिषेक किया जाएगा। साथ ही सुख शय्या धीवास का आयोजन भी होगा।

कार्यक्रम के तृतीय दिवस 21 फरवरी शुक्रवार को सभी देवी-देवताओं का पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा, शिखर कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद पूर्णाहुति एवं आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन रखा गया।

मुख्य अतिथि के रूप में महंत श्री 1008 दयाराम दास जी महाराज (दाड़की वाले बाबा) श्री हनुमंत निवास आश्रम पीपल खुंटा धाम, संत श्री कानु महाराज हाट केश्वर धाम सेमलिया, यज्ञाचार्य पं राहुल शर्मा (उज्जैन वाले), यज्ञ संयोजक पं कृष्णा त्रिवेदी (नानपुर वाले) एवं स्थानीय पंडित संजय ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। शिव भक्तों ने नगरवासियों से इस धार्मिक आयोजन का लाभ लेने की अपील की है।

मध्यप्रदेश की जीवन रेखा पर प्रदुषण का खतरा पेयजल के लिए घातक

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, मोक्षदायिनी मां नर्मदा का जल प्रदुषित होता जा रहा है, प्रदुषण नियंत्रण मंडल के द्वारा जारी रिपोर्ट में 50 स्थानों में से 15 स्थानों पर नर्मदा नदी का पानी पिने योग्य नहीं होना प्रदेश के लिए घातक है। निश्चित ही नर्मदा नदी की स्वच्छता के सारे सरकारी अभियानों को इस रिपोर्ट से जोरदार झटका लगा है। क्योंकि पिछले एक वर्ष में नर्मदा नदी का प्रदुषण कम होने के बदले और बढ़ गया है, जो कि स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि, नर्मदा नदी की स्वच्छता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लंबे चौड़े बजट की परियोजनाओ की प्रगति नगण्य है। अर्थात की प्रदेश सरकार ने नदी की स्वच्छता के लिए करोड़ो रुपए जो प्रतिवर्ष खर्च किए उसके परिणाम शुन्य है।

प्रदुषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट के अनुसार नरसिंहपुर के बाद से 15 स्थानों पर नर्मदा नदी का जल पिने योग्य नहीं बचा है। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम से बुधनी सिहोर तक रिपोर्ट में जल को बी श्रेणी में रखा है, वहीं उज्जैन के पास नेमावर से आलीराजपुर तक ए श्रेणी में जल को रखा गया है।

प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने रामघाट अनूपपुर से लेकर आलीराजपुर तक 50 स्थानों से नर्मदा जल का सेंपल लिया था, मंडल को जांच में 15 स्थानों का जल पिने योग्य नहीं मिला। चिंताजनक बात यह है कि, वर्ष 2022-2023 की जांच में इन सभी 50 स्थानों पर नर्मदा का जल पिने योग्य था और ए श्रेणी में था किंतु एक वर्ष के भीषण प्रदुषण ने मां नर्मदा को दुषित कर दिया। ध्यान रखने योग्य बात तो यह है कि यह प्रदुषण उस समय बढ़ रहा है जब सरकार नर्मदा नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए नमामि नर्मदे सहित कई अभियान चला रही है।

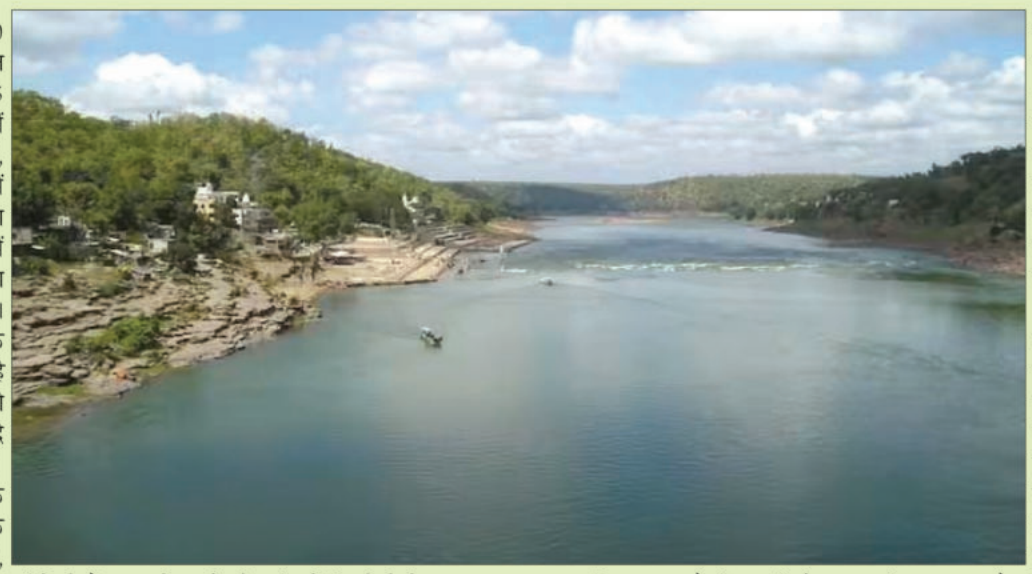

प्रदेश सरकार और एनजीटी के अनुसार नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहें हैं, मगर परिणाम तो घटते क्रम में दिखाई दे रहे हैं। एनजीटी के निर्देशानुसार नर्मदा नदी में मिलने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत प्रदुषण नियंत्रण मंडल द्वारा लोगों को गंदगी नहीं करने के लिए जागरुक किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा पालीथीन जब्ती की कार्रवाही की जाती है, और उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नर्मदा में मिलने से रोका जा रहा है, फिर भी नर्मदा का जल दिन प्रतिदिन दुषित होता जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 17 स्थानों से प्रतिमाह नर्मदा नदी के जल का सेंपल लिया जाता है, इन स्थानों पर नर्मदा के पानी का किटानुशोधन होता है जिसके बाद उसे पेयजल में उपयोग किया जाता है।

प्रासंगिक प्रश्न है कि, नदी के जल की स्वच्छता के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने, और नमामि गंगे मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण एवम रिवर फ्रंट डेवलपेंट, जैसी योजनाओं को संचालित करने के बाद भी स्थिती में सुधार क्यों नहीं होता। सरकारी तंत्र या प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में लचक या जिम्मेदारी से काम नहीं किए जाने की लत या फिर नागरिको में जागरुकता लाने का अभाव। यदी लचरता इसी प्रकार रही तो मध्यप्रदेश में लोग जिस नर्मदा नदी का जल पी कर जीवित है उसकी अनदेखी दूर नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं होगा जब शुद्ध पेयजल के लिए सबको तरसना पड़ेगा।

प्रदेश के हर जिले में कोई न कोई छोटी बड़ी नदी बहती ही है, उन नदियों में भी यहीं समस्या जड़ता से जमी हुई है, प्रत्येक नदी में शहर, नगर की सीवेज लाईन जा कर मिलती है और नदी के स्वच्छ जल को दुषित करती है। उद्योगो का गंदा केमिकल युक्त कचरा और दुषित पानी नदी के स्वच्छ जल को प्रदुषित कर रहा है। विकासशीलता के नाम पर नदी के प्रवाह को समाप्त किया जा रहा है।

वर्तमान में यह समस्या सरकार को चाहे छोटी लग रही हो परंतु आने वाले कुछेक वर्षों में ही इस समस्या के परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते है। नदियों की स्वच्छता पर सरकार ने गंभीरता से कार्य को बल नहीं दिया तो जल्द ही छोटी नदियों की तरह नर्मदा नदी का जल भी पेयजल के योग्य नहीं रहेगा, जब एक वर्ष में ही 50 में से 15 स्थानों पर नर्मदा का जल दुषित होकर पिने योग्य नहीं रहा तो आने वाले वर्ष में सरकार को यह चुनौती होगी की उन स्थानों के जल को फिर से पेयजल के योग्य बनाकर उसे ए श्रेणी में स्थापित करे।

रिकेश बैरागी

विचारणीय है कि, सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, उसके पहले ही नर्मदा के जल में प्रदुषण के अनेक कारण सामने आ रहे हैं, औद्योगिक उपक्रमों के साथ ही खेतों में रसायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग से भी नर्मदा जल जहरीला हो रहा है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की गंभीरता जितनी संवेदनशीलता प्रदेश सरकार नदियों की स्वच्छता के प्रति प्रदर्शित करेगी तब ही श्रेणी सुधार होने की संभावना है।

बहरहाल यह स्थिती तब है जब मध्यप्रदेश विधानसभा में मोक्षदायिनी मां नर्मदा नदी को जीवन इकाई मानने का संकल्प पारित किया जा चुका है।

संपादकीय

बचपन पर भारी स्मार्ट फोन

तकनीक के जरिये विकास की अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खो भी रहे हैं। इंसान कभी मशीन से संचालित नहीं हो सकता। मानवीय संवेदनाएं और अहसास कभी कृत्रिम नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई तकनीक, मशीन व उपकरण सहयोगी तो हो सकते हैं, मगर मालिक नहीं हो सकते। कमोबेश यही बात शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर कही जा सकती है।

निःसंदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नई शैक्षिक परिपाटी में मोबाइल की अपरिहार्यता को महंगे स्कूलों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं खड़ी कर रहा है। निस्संदेह, विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फोन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। तब लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही है। जाहिरा तौर पर ये उनके भटकाव और मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। अब इसके मानसिक व शारीरिक दुष्प्रभावों पर व्यापक स्तर पर बात होने लगी है। यहां तक कि आस्ट्रेलिया समेत तमाम विकसित देश स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर रोक लगा रहे हैं।

अब तो यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की दुनिया में शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने वाली टीम ने भी स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इसकी रिपोर्ट भारत में शिक्षा के नीति-नियंताओं की आंख खोलने वाली है। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ कदमताल की दलील देकर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके निरंकुश प्रयोग का है। साथ ही दुनिया में बेलगाम इंटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। जिसमें प्रश्न बच्चों की निजता का भी है। वहीं प्रश्न ज्यादा प्रयोग से बच्चों के दिमाग व शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भी है। निस्संदेह, शिक्षकों व अभिभावकों की देखरेख में सीखने की प्रक्रिया में स्मार्टफोन का सीमित उपयोग तो लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफोन में वयस्कों से जुड़े तमाम एप ऐसे भी हैं जो समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रहे हैं। उन्हें यौन कुंठित बना रहे हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। बच्चों में याद करने की क्षमता घट रही है। ऐसे में जब शिक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है। निस्संदेह उसका उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। संकट यह भी कि मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑन लाइन गेम जहां बच्चों को मैदानी खेलों से दूर कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर फोन छात्र-छात्राओं का सहायक तो बन सकता है, लेकिन उनके दिमाग को नियंत्रित करने वाला नहीं।

भूकंप की आशंकाओं संग जीने का तरीका तलाशें

भूकंप की चर्चा अक्सर तब होती है, जब वह किसी इलाके में आ जाता है। इसकी पुनरावृत्ति और इससे बचाव की तैयारियों की चर्चाएं कुछ दिन तक चलने के बाद खामोश हो जाती हैं। दुनिया अपनी पहली सी चाल में व्यस्त हो जाती है और भूकंप अदालत में चल रहे किसी मामले की तरह एक अगली तारीख के लिए मुल्तवी हो जाता है। जैसे, सोमवार की सुबह देश का राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र एक जलजले की आहट से चौंक उठा। रिक्टर स्केल पर चार की तीव्रता वाला भूकंप दहलाकर चला गया, लेकिन महीना भर पहले ही पड़ोस में तिब्बत के भूकंप ने एक बड़ी चेतावनी हमें दी थी।

हिमालय और इससे सटे हुए इलाकों में भूकंप का आना एक बड़ी चेतावनी माना जाता है, पर हफ्ता बीतते-बीतते भूकंप की खबर और चिंता हवा हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि कुछ ही समय पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने और मिशन मौसम की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाने और चेतावनी देने वाली प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया था। उद्देश्य है कि पूर्वानुमानों से भूकंप की त्रासदी को सीमित किया जा सके।

यह सुखद है कि तमाम दावों के बावजूद मोटे तौर पर 2015 के बाद से उत्तर भारत में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हालांकि, बार-बार चेताया गया है कि पर्वतीय राज्यों- खास तौर से उत्तराखंड से लेकर हमारे देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर की जमीन के भीतर बहुत अधिक खिंचाव की स्थिति बन गई है और यहां कभी भी ज्यादा ताकत वाला भूकंप आ सकता है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसलिए जान-माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है। वहीं इस चेतावनी का समर्थन कुछ मौकों पर आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों ने भी किया है। इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है। इससे वहां बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा हो गई है और वह कभी भी बड़े विस्फोट के साथ बाहर निकल सकती है। जो बड़े भूकंप का कारण बनेगी। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हिंदुकुश पर्वत से पूर्वोत्तर भारत तक के हिमालयी क्षेत्र को भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा है कि खतरों से निपटने के लिए संबंधित राज्यों में कारगर नीतियां नहीं हैं।

निःसंदेह, धरती के अंदर चल रही भूगर्भीय हलचलों के कारण ज्वालामुखी विस्फोटों से लेकर भूकंपों तक का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल यह है कि धरती पर करीब 10 करोड़ भूकंप हर साल आते हैं, लेकिन उनमें से नुकसान पहुंचाने वाले भूकंपों की संख्या बेहद कम है। दशकों से भूगर्भ वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि भले ही बड़े भूकंप की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

लेकिन सवाल उठता है कि क्या भूकंपों की पूर्व सूचना देने का तंत्र विकसित नहीं हो सकता। निस्संदेह, वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद इंसान आज भी धरती के अंदर की हलचलें पहले से पढ़ पाने में नाकाम ही है।

चार साल पहले ऐसी एक पहल उत्तराखंड में की गई थी। वहां साल 2021 में आपदा प्रबंधन विभाग और आईआईटी रुड़की ने मिलकर उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप तैयार किया था। दावा किया गया था कि भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले एप को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। कहा गया कि जिन लोगों के पास सामान्य स्मार्टफोन नहीं हैं, उन्हें भी उनके फीचर फोन पर भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। लोग समय रहते उससे बचाव का प्रबंध कर सकेंगे। यह देखते हुए कि पिछले 10-15 वर्षों में उत्तराखंड भूकंप के करीब 700 झटके झेल चुका है, इस ऐप को एक बड़ी उम्मीद माना गया था। लेकिन हकीकत में इस ऐप से उत्तराखंड निवासियों को कोई मदद नहीं मिल सकी।

दरअसल, हिमालय क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है और वहां धरती के भीतर जिस तरह की हलचल मची हुई है, उसमें भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। निस्संदेह, भारत में अभी भूकंप की चेतावनी का कोई विश्वसनीय सिस्टम बना नहीं है और हमारी सरकार तक यह कह चुकी है कि दुनिया में ही इसका कोई कारगर सिस्टम नहीं है। निश्चय ही कोई भी देश, संगठन या वैज्ञानिक अभी दावे के साथ यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि वे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का एकदम सही पूर्वानुमान पेश कर सकते हैं। इस चिंता ने लोगों को और ज्यादा सतर्कता बरतने को विवश कर रखा है।

एक घटना इटली में भूकंप के पूर्वानुमान से जुड़ी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को ही बेचैन कर दिया था। असल में डेढ़ दशक पहले (वर्ष 2011 में) वहां छह साइंटिस्टों और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था क्योंकि वे छह अप्रैल, 2009 को इटली के ला-अकिला में आए भूकंप की सही भविष्यवाणी करने में नाकाम रहे थे। ये सभी इटली में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे पर नजर रखने वाली समिति के सदस्य थे। इन्हें ला-अकिला में भूकंप से ठीक एक दिन पहले यह जांच करने बुलाया गया था कि क्या वहां बड़े भूकंप का कोई खतरा तो नहीं है। उस इलाके में निकल रही रेडॉन गैस की मात्रा के आधार पर इन साइंटिस्टों ने आश्वस्त किया था कि फिलहाल खतरा ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके को खाली कराया जाए। पर अगले दिन वहां 6.3 की ताकत वाला बड़ा भूकंप आ गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

दुनिया के हजारों साइंटिस्टों ने साझा बयान में इस मुकदमे का विरोध किया था। उनका कहना था कि साइंटिस्टों को बलि का बकरा बनाने के बजाय भूकंप से सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भूकंप की पक्की भविष्यवाणी करने की कोई विधि अभी तक विकसित नहीं हो सकी है।

डॉ. संजय वर्मा

जहां तक रेडॉन गैस की बात है तो वह भूकंप की भविष्यवाणी करने की विवादास्पद प्रणाली है, कई बार गलत भी साबित हुई है।

बहरहाल, पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि कब, किस जगह पर कितना बड़ा भूकंप आएगा। असल में भूगर्भीय प्लेटों के परस्पर जुड़ने, धराखंड से अलग होने और टूटन-चटकने के कारण भूमिगत ताप, दाब संवेग और रासायनिक क्रियाओं और इस कारण पैदा हुई ऊर्जा तरंगों का एक विकृत रूप हमें भूकंप की शक्ल में जब-तब देखने को मिलता है। हालांकि भूकंपों से अगर हम कोई सबक लेना चाहें, तो वह हमें इस आपदा से काफी हद तक सुरक्षित कर सकता है। दिल्ली और एनसीआर का बड़ा हिस्सा भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। साथ ही, उत्तराखंड, उ.प्र. और पूरा बिहार खिसकती हुई हिमालयी प्लेट के हिस्से हैं। भूकंप से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सतर्कता और बचाव के इंतजाम करना। कई देशों के उदाहरण इस संदर्भ में दिए जा सकते हैं। जैसे, अल्जीरिया में ज्यादातर स्कूलों और रिहाइशी इलाकों की इमारतें सीस्मिक बिल्डिंग कोड के तहत बनाई गई हैं। इसी तरह कनाडा का अपना राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड है और वहां अस्पताल, स्कूल व अन्य सरकारी-रिहाइशी इमारतें इसी के तहत बनाई जाती हैं। मध्य अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका स्कूल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम के तहत स्कूलों की बिल्डिंग्स को खतरे से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिली के स्कूलों में बच्चों को साल में तीन बार भूकंप से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। चिली के 2010 के 8.8 तीव्रता के भूकंप में स्कूलों को सबसे कम नुकसान इसीलिए हुआ था क्योंकि इमारतें बिल्डिंग कोड का पालन करती थीं।

आस्था, शिष्टाचार और महाकुंभ का बाजार

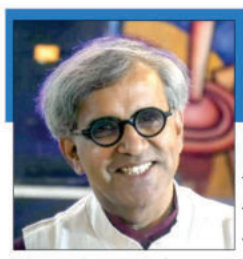

आलोक कुमार पुराणिक

स्मार्ट विश्वविद्यालय ने महाकुंभ विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध इस प्रकार है:-

कुंभ का मतलब घड़ा होता है, घड़े का भारतीय राजनीति, धर्म और दर्शन में गहरा महत्व है।

राजनीति में घड़े का महत्व यह है कि उन नेताओं का आदर्श माना जाता है, जो चिकने घड़े की तरह हों, यानी जिनके ऊपर पानी ठहरता ही न हो।

महाकुंभ का भी गहरा राजनीतिक महत्व है। तमाम तरह के नेता तमाम तरह के बयान रोज देते हैं महाकुंभ पर। महाकुंभ निपट जायेगा, इसके बाद तमाम नेताओं को बेवकूफाना बयान देने के लिए नये विषय तलाशने पड़ेंगे।

महाकुंभ के कारण प्रयागराज के अंदर और प्रयागराज के बाहर लंबे-लंबे जाम लग लिये हैं। इतने लंबे-लंबे जाम कि छोटे नन्हे देशों में भारतीय राजदूत इन छोटे नन्हे देशों के प्रधानमंत्री के सामने तड़ी लगा सकते हैं कि जितना क्षेत्रफल आपके पूरे देश का है, उतने क्षेत्रफल में हमारे महाकुंभ के जाम लगते हैं। या यह गर्वोक्ति भी भारतीय कर सकते हैं कि जितनी पॉपुलेशन सिंगापुर या न्यूजीलैंड की है, उस पॉपुलेशन की सौ गुना पॉपुलेशन तो कुंभ में स्नान कर चुकी है।

कई-कई दिनों तक जाम में फंसकर भारतीय पब्लिक जान बचा सकती है, यह देखकर अमेरिकन सरकार अपने कमांडो लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रयागराज भेजने की तैयारी कर सकती है। भारत की पब्लिक इस तरह के हालात में भी बखूबी जीवित रह सकती है, यह बात कई यूरोपीय देशों की पब्लिक को भरोसा दिला देती है कि भारत चमत्कारों की भूमि है।

कुंभ इतिहास भी है, कुंभ दर्शनशास्त्र है, कुंभ राजनीति है। कुंभ का ताल्लुक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी है। कई विदेशी राजनयिक भी कुंभ में नहाने जा रहे हैं। कई देशों के राजनयिक यह देखकर परेशान हैं कि उनके मुल्क की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग यहां नहाने क्यों आते हैं। नहाना कई देशों में बहुत गैर-जरूरी बात मानी जाती है। कई यूरोपीय देशों में तो कई-कई दिनों तक न नहाना उतना ही नार्मल है, जितना किसी भी भारतीय नेता का भ्रष्टाचार करना।

कुंभ मार्केटिंग का भी महोत्सव है। कई कंपनियां अपने ब्रांडों को जमाकर कुंभ का पुण्य हासिल करना चाहती हैं। कंपनियों और नेताओं में एक समानता है, जहां भी पब्लिक जुटती है, वहां ये अपना माल बेचना चाहते हैं।

पहले लोग कुंभ नहाने जाते थे, चुपके से नहा-धोकर वापस आकर अपने काम-धंधे में लग जाते थे। अब लोग कुंभ जाते हैं और उसकी फोटू सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो कुंभ में जाये बगैर ही कुंभ स्नान की फोटो डाल देते हैं।

अपने एआई इकोसिस्टम को मजबूत करें

पिछले दिनों चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डीपसीक आर-1 ने आते ही अमेरिका सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। डीपसीक ने अमेरिका के एआई वर्चस्व को तोड़ते हुए एनवीडिया सहित कई अमेरिकी टेक कंपनियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने काफी कम खर्च में इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाया है, जिसके बारे में दुनियाभर के एआई एक्सपर्ट सोच ही नहीं सकते थे कि चीन भी ऐसा कर सकता है। अब इस एआई ने पूरी दुनिया के टेक महारथियों को हिलाकर रख दिया है।

चाइनीज़ स्टार्टअप कंपनी ने एक एआई चैट मॉडल, डीपसीक आर -1 पेश किया। इस चाइनीज़ एआई मॉडल ने एआई एफिसिएंसी, लागत में कमी और स्केलेबिलिटी में शानदार सफलता प्राप्त की है। चीनी कंपनी डीपसीक ने इन खर्चों में 94 प्रतिशत की कटौती की और सिर्फ 6 मिलियन डॉलर के ट्रेनिंग खर्च के साथ एक पॉवरफुल एआई मॉडल बना लिया। एआई मॉडल को बनाने के लिए खर्च को 94 प्रतिशत तक कम करना पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात है। डीपसीक ने इसके लिए कई क्रांतिकारी तकनीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, ओपन एआई 32-बिट फ्लोटिंग प्वाइंट्स का उपयोग करता है, जिसमें एक संख्या को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी की आवश्यकता होती है। डीपसीक एआई मॉडल 8-बिट फ्लोटिंग प्वाइंट्स का उपयोग करता है, जिससे इसकी मेमोरी की जरूरतें कम हो जाती हैं। इसे सिर्फ 1 बाइट मेमोरी की आवश्यकता होती है।

दुनिया की शीर्ष कंपनियां आमतौर पर अपने चैटबॉट को सुपरकंप्यूटर से प्रशिक्षित करती हैं, जिसमें 16,000 या उससे ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल होता है। डीपसीक के इंजीनियरों ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ 2,000 एनवीडिया चिप्स की ज़रूरत थी। दुनियाभर के ज्यादातर एआई मॉडल्स एक बार में एक ही शब्द को पढ़ते हैं और प्रोसेस करते हैं, लेकिन डीपसीक एक बार में पूरे वाक्य को पढ़ सकता है और प्रोसेस कर सकता है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाता है। चैट जीपीटी-4 को एक जवाब देने में दो सेकंड लगते हैं, जबकि डीपसीक के लिए दावा किया गया है कि यह 90 प्रतिशत सटीकता के साथ एक सेकंड में जवाब दे सकता है।

दरअसल, एआई मॉडल ट्रेनिंग साइकिल के दौरान अरबों शब्दों को प्रोसेस करते हैं। ऐसे में प्रोसेसिंग टाइम को कम करना, इस एआई कंपनी के लिए बड़ी सफलता है। ओपन एआई का जीपीटी-4 हर कैल्कुलेशन के दौरान 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को एक्टिव रखता है। वहीं, डीपसीक एक एडवांस एल्गोरिथ्म का उपयोग करके सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे को एक्टिव करता है। इससे एक समय में सिर्फ 37 बिलियन सक्रिय पैरामीटर्स होते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि ओपन एआई की तुलना में डीपसीक के एआई मॉडल्स में किसी क्वेरी के प्रति कैल्कुलेशंस की संख्या काफी कम हो जाती है। यह मॉडल इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि टेस्ला के पूर्व एआई निदेशक आंद्रेज करपैथी ने कहा कि डीपसीक ने कम बजट में एक एआई मॉडल को प्रशिक्षण देना बहुत आसान बना दिया है।

वर्ष 2022 के अंत में जब ओपन एआई ने एआई बूम की शुरुआत की, तब से प्रचलित धारणा यह थी कि विशेष एआई चिप्स में अरबों डॉलर का निवेश किए बिना सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब यह होगा कि केवल सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, ही अग्रणी तकनीकों का निर्माण कर सकती हैं। डीपसीक के आने के बाद अब तस्वीर बदल गई है, ये लगने लगा है कि एआई मॉडल को कम पैसे में भी बना सकते हैं। डीपसीक विशेषज्ञों के अनुसार उन्हें अपने नए सिस्टम को तैयार और ट्रेंड करने के लिए केवल 6 मिलियन डॉलर की कच्ची कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता थी। यह मेटा द्वारा अपनी नवीनतम एआई तकनीक बनाने में खर्च की गई राशि से करीब 10 गुना कम था।

डॉ. शशांक द्विवेदी

दरअसल, यह शानदार उपलब्धि सिर्फ एआई रिसर्च और व्यवसायों के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी भारी महत्व रखती है। निःसंदेह, एआई टेक्नोलॉजी अब युद्ध की रणनीतियों को भी बदल रही है। चीन के पास पहले से ही एक एडवांस साइबर युद्ध सिस्टम है। एआई की मदद से चीन सोशल मीडिया पर असली जैसी दिखने वाली झूठी कहानियां तेजी से फैला सकता है, ताकि लोगों की राय, मानसिकता और कानूनी युद्ध को प्रभावित किया जा सके। इसके कारण भारत की एकता पर भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा चीन अपनी डीपसीक वाली एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हैकिंग टूल्स भारत के रक्षा ढांचे, परमाणु सुविधाओं और फाइनेंशियल सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। भारत को अपने एआई इकोसिस्टम को जल्द से जल्द मजबूत करने की जरूरत है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना, एआई द्वारा संचालित रक्षा तकनीक को प्राथमिकता देना काफी महत्वपूर्ण है।

छुटभैया नेताओं की गाड़ियों में लगे हूटर, प्रशासन की आंखों पर बंधी काली पट्टी

माही की गूंज, शुजालपुर।
अजय राज केवट

जिले में, ''अंधेर नगरी चौपट राजा'' की कहावत सही सिद्ध होती दिख रही है। शुजालपुर शहर में सरपंच प्रतिनिधि से लेकर छुटभैया नेता, माफिया, गुंडों तक ने अपने वाहन में हूटर लगाकर रौब झाड़ रहे है। ओर शहर में वर्तमान में हूटर लगाकर रौब झाडने वालों छुटभैये नेताओं की बाढ़ सी आ गई। नियम कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। फिर भी जिम्मेदार अफसरों की बड़ी लापरवाही यह है कि इस ओर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधियों की हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने कुछ साल पहले मंत्री, अफसर सहित जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर हूटर लगाने के नियम को बंद कर दिया था। जब से हूटर लगाने का नियम बंद हुआ है, तब से जिले में हूटर लगाने छूटभैए नेताओं की बाढ़ सी आ गई। इसमें सरपंच प्रतिनिधि से लेकर कई छूट भैय्या नेता भी शामिल है।

माही की गूंज की टीम ने सोमवार को इसकी पड़ताल की तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए। एक चौराहे में आधे घंटे तक खड़े हुए तो दर्जन भर से ज्यादा हूटर लगे हुए वाहन नजर आए। जब जिला मुख्यालय की शुजालपुर तहसील का यह हाल हैं तो ओर जिले का क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी वजह जानने के लिए अफसरों से संपर्क किया गया तो दबे जुबान पर कहा कि मंत्री, विधायक से जुड़े हुए लोग है। इसके अलावा अधिकांश प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि है। राजनीतिक दबाव के चलते ऐसे हूटरबाजों से कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक को देखकर अन्य दूसरे जनप्रतिनिधि ने भी अब हूटर लगाने का फ़हशन बना लिया जब तक इन पर अभियान चलाकर कार्रवाई नहीं होगी तो तब तक यह बंद नहीं होंगे। इसके बाद कई दुकान जाकर देखा गया तो आसानी से हूटर मिल जाता है। इन दुकानदारों को भी कार्रवाई होने का कोई डर नहीं है। ऐसे में खुलेआम बेच रहे हैं।

बड़ी लापरवाही, सालभर में एक भी कार्रवाई नहीं

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो साल में एक भी हूटर लगे वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस व यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस व यातायात विभाग का अमला दिन भर अवैध वसूली में मस्त रहता है

केन्द्रीय मोटरयान नियम 119 में तय किया है। जिसमें एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, आकस्मिक सेवा में चलने वाली गाड़ी और परिवहन विभाग के अफसरों की गाडियों पर हूटर लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के नियम में भी ऐसा ही है। इसके बावजूद नियम का जिले

में कहीं पालन नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा नियम भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि वा छूट भैय्या नेता ही तोड़ रहे हैं।

मंडल कंमडल अध्यक्षों ने भी लगाए हूटर

बिना परमिशन के चलते शहर में गुंडों माफियाओ से लेकर मंडल कंमडल अध्यक्षों ने भी शहर में हूटर बजाकर अपनी नेतानगरी चमकने में लगे हुए है। मगर न तो इस ओर यातायात ट्रैफिक पुलिस जवानों की नजर हे न शहर के बड़े अधिकारी की ट्रैफिक जवान तो काला चश्मा लगाकर कर अवैध वसूली में मस्त हे। चौराहे पर अपनी बाइक खड़ी कर चिल की तरह ताकते रहते बालू रेत के डंपर किधर से आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि, खबर प्रकाशन के बाद में जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुलती है या नहीं या कुंभकर्ण नींद सोते रहेंगे और हूटर बाज छूट भैया नेता शहर में हुडदंग मचाते रहेंगे।

अवैध शराब की गाड़ी रोकने गए सैलाना विधायक से मारपीट साथियों को पीटा

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मंगलवार रात फिर शराब से भरी गाड़ी पकड़ी तो विवाद हो गया। विधायक ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। वीडियो जारी कर कहा कि मेरा गला दबाने का प्रयास किया। मेरे और मेरे साथियों के साथ मारपीट हुई है। विवाद के बाद गाड़ी का ड्राइवर भी थाने पहुंच गया है। ड्राइवर ने भी विधायक और उनके साथ आए लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के परनाला के पास का है।

विधायक ने अपने समर्थकों के साथ शराब से भरी एक गाड़ी (पिकअप) को रोका। ड्राइवर से पूछताछ की तो विवाद हो गया। विधायक और उनके साथ आए लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस दौरान विधायक के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट हुई।

विधायक ने अपने ऊपर हुए हमले की सूचना पहले बाजना पुलिस को दी। बाजना पुलिस थाने से निकली। विवाद का क्षेत्र शिवगढ़ थाना क्षेत्र होने से पुलिस लौट गई। मौके पर शिवगढ़ थाने की पुलिस पहुंची। बाद में विधायक और शराब से भरी गाड़ी का ड्राइवर शिवगढ़ थाने पर आए। रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया भी शिवगढ़ थाने पहुंचे। विधायक डोडियार शिवगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल के लिए पहुंचे। वहीं ड्राइवर और क्लीनर भी देर रात शिवगढ़ थाने में मौजूद रहे।

देर रात तक दोनों ओर से थाने पर आवेदन देने की बात कही जा रही थी। वहीं, मंगलवार रात 11:00 बजे के लगभग पुलिस मामले की जांच में सामने आया कि पिकअप क्रमांक एमपी 13 जीबी 2215 में 130 पेटी अंग्रेजी शराब थी, जो जावरा के सरकारी वेयर हाउस से बाजना के केलकच्छ जा रही थी। शराब का परमिट भी था। देर रात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी रही।

लहसुन के लगातार भाव गिरने से आक्रोशित हुए किसान

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के मल्हारगढ क्षेत्र में किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ उंटी एवं देशी लहसुन बोई थी कि अच्छे दाम मिलेंगे और सामाजिक कार्य के साथ ही लेन देन भी हो जायेगा लेकिन लहसुन के दाम लगातार गिरने से किसानों के साथ ही व्यापारियों की भी नींद उड़ाकर रख दी है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे मल्हारगढ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा आदि ने गांवों में खेतों में पहुंच कर लहसुन उत्पादक किसानों से चर्चा की।

सुपड़ा के किसान प्रहलाद पाटीदार ने बताया कि, मेंने 14 क्विंटल उंटी लहसुन, 50 हजार रुपये क्विंटल में बीज लाकर सात बीघा में बोई थी जो 7 लाख रुपये का था ओर तीन लाख पचास हजार रुपये हकाई जुताई बुआई कीटनाशक छिड़काव व लहसुन कटाई का खर्चा हो गया।ओर लहसुन 4 से 6 हजार ही बिक रही है यह बड़ा घाटा है परिवार में मांगलिक कार्य भी है बीज भी इधर उधर से कर्ज लेकर लाया था और अब बीज का पैसा भी निकलना मुश्किल ही लगरहा है खेती किसानी बहुत घाटे का धंधा होने लगा है।

किसान बाबुखा मेवाती ने बताया कि, मैने दस बीघा में उंटी एवं देशी लहसुन बोई थी आज उंटी लहसुन कृषिउपज मंडी में लाकर बेची जो मात्र 4800 रुपये क्विंटल ही बिकी काफी नुकसान हुवा ओर आगे भी अच्छे भाव मिलने की उम्मीद नही है लागत मूल्य तो दूर मजदुरो की मजदूरी भी व फसल पर होने वाला खर्च भी मिलना कोसो दूर की बात है।

मल्हारगढ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि, किसानो को भाजपा सरकार में लहसुन सहित अन्य फसलों के वाजिब दाम नही मिलने से किसान खून के आंसू बहाने पर मजबूर है, शर्मा ने कहा कि सरकार की मिलीभगत से ही चाईना की लहसुन अफगानिस्तान के रास्ते भारत आरही है इस कारण भी यहां के किसानों व व्यापारियों को दुःखी एवं परेशान होना पड़ रहा है, उन्हें अच्छे भाव नहीं मिला रहे हैं।

काँग्रेसजनों ने किसानों एवं महिलाओं के साथ लहसुन के भाव नहीं मिलने पर अनूठा प्रदर्शन किया खेत मे उखाड़ी हुई उंटी कि लहसुन को जोकि मृत ही हो चुकी है उसपर सफेद कपड़ा कफन ओढ़ाकर पुष्पमाला व पुष्पांजलि अर्पित कर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार से उपज के अच्छे भाव की मांग की।

अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के लिए ग्राम में लगाए गए 34 सीसीटीवी कैमरे

माही की गूंज, शाजापुर।

अपराधों की रोकथाम और पतारसी के लिए आज के समय में सीसीटीवी कैमरों की निर्णायक भूमिका है इसी उद्देश्य से शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले में अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलेभर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय संस्थानों और संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है।

इसी दिशा में, थाना मोहन बड़ोदिया के ग्राम दुधाना पंचायत में सरपंच राकेश जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रेरणा लेकर पूरे दुधाना कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की पहल की है। इस पहल के तहत कस्बे में कुल 34 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी शुरुआत आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के द्वारा की गई। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मुख्य मार्गों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी प्रभावी रूप से की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, पूरे कस्बे में वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे तकनीकी रूप से उन्नत सुरक्षा प्रणाली को और अधिक कारगर बनाया जा सकेगा।

इन सीसीटीवी कैमरों की सहायता से अपराधों की रोकथाम और घटनाओं की निगरानी करना संभव होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे अपराधियों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। साथ ही, निर्दोष व्यक्तियों को गलत आरोपों से बचाने में भी ये कैमरे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की आधुनिक निगरानी प्रणाली एक मील का पत्थर साबित होगी। दुधाना ग्राम में उठाए गए इस कदम से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे भी अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में पहल कर सकें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाजापुर द्वारा बताया गया कि, शाजापुर पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम के लिए सतत प्रयासरत है और भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

20 फरवरी से मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन

माही की गूंज, मंदसौर।

मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा मंगलवार को प्रभारी अधिष्ठाता, सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर को 20 फरवरी 2025 से मांगों को लेकर शुरू होने चरणबद्ध आंदोलन के संबंध ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सौरभ जैन एवं सचिव डॉ. ईशांत चौरसिया ने बताया कि म.प्र. शासकीय-स्वशासी चिकित्सक महासंघ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग एवं गैस राहत विभाग में कार्यरत 15,000 चिकित्सकों एवं जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता हैं। चिकित्सक महासंघ की कार्यकारिणी समिति की 16 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में 7 घटक संगठनों के प्रदेश स्तर, संभाग स्तर एवं जिले स्तर के उपस्थित 150 चिकित्सकों ने सर्वसम्मति से दिनांक 20 फरवरी 2025 से प्रदेशव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अनुक्रम में इस संस्था में कार्यरत शासकीय चिकित्सक महासंघ के चिकित्सकों की 18 फरवरी मंगलवार को आयोजित पल्स जीबीएम/ सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से चिकित्सक महासंघ की कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसरण में निम्नानुसार क्रमबद्ध आन्दोलन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया हैं जिसके अंतर्गत 20 एवं 21 फरवरी को काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 22 फरवरी को आधे घंटे कार्यस्थल के बाहर टोकन विरोध प्रदर्शन (इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी)। साथ ही चिन्हित अस्पतालों पर अमानक दवाइयां की सांकेतिक होली जलाई जाएगी। 24 फरवरी को प्रदेशव्यापी ह्यसामूहिक उपवासह्य कर अन्न त्याग के साथ 01 घंटे कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन (इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी)। 25 फरवरी से प्रदेशव्यापी प्रशासनिक असहयोग आंदोलन किया जाएगा।

जमीन पर लोट लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिला

माही की गूंज, मंदसौर।

स्वामित्व योजना में अपना नाम न जुड़ने से परेशान एक महिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लोट लगाते हुए पहुंची। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने उसे उठाया और एडीएम से मिलवाया। साठखेड़ा ग्राम की पूजा पति अनिल धाकड़ अपने मकान का नाम स्वामित्व योजना में जुड़वाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थीं। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उन्होंने सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पूजा का कहना है कि, उन्होंने कई बार पटवारी और तहसीलदार के पास जाकर आवेदन दिया, रजिस्ट्री और रसीदें प्रस्तुत कीं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

प्रशासन की उदासीनता से निराश होकर पूजा ने कलेक्टर कार्यालय में लोट लगाकर विरोध जताया। महिला को लोट लगाते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और उसे रोका। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। अपर कलेक्टर ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किए गए सर्वे में महिला का नाम छूट गया था, लेकिन अब लिंक चालू है और जल्द ही उनका नाम जोड़ा जाएगा। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनसुनवाई में छाया सन्नाटा, कोर्ट ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील

पूजा धाकड़ को अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाता है, जिससे भविष्य में किसी नागरिक को इस प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूजा धाकड़ ने कहा कि मैंने पंचायत, पटवारी और तहसीलदार के कई चक्कर काटे मेरे पास सभी जरूरी कागज-दस्तावेज और प्रमाण पत्र सब हैं, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। मैं गरीब हूं और मैंने बहुत मेहनत करते हुए रकम जोड़ी है ताकि मैं मकान ले सकूं, लेकिन मंदसौर प्रशासन के अफसर, पटवारी और तहसीलदार मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं कर रहे।

माही की गूंज के समाचार पर हो जाती कार्रवाई तो विभाग की नहीं होती किरकिरी

मामला: भ्रष्ट बीआरसी को लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़ने का

माही की गूंज झाबुआ/थांदला

कहावत है कि, किसी कुत्ते की दाढ़ में एक बार खून लग जाए तो वह कुत्ता खून चाटने के बिना नहीं रह सकता है। इसी तर्ज पर हमारे तंत्र में किसी को भी रिश्वत लेने की आदत बन चुकी है तो वह बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता है। वही यह भी कहावत है कि ÷धान के साथ धनेरिया भी पिसाता है÷।

कुछ ऐसा ही वाक्या झाबुआ जिले के थांदला में खंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) एवं चपरासी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़े। बात करें थांदला बीआरसी संजय सिकरवार की तो, वह बीआरसी के पूर्व थांदला ब्लॉक के कुकड़ीपाड़ा संकुल का प्रभारी प्राचार्य था। यहां पर भी प्रभारी प्राचार्य रहते हुए मनमानी के साथ कार्य करता था और अपनी मर्जी से आता व जाता था। यहीं से इसे रिश्वत लेने की बडी चाट लग गई थी और बड़ी रिश्वत मिलने की आस के साथ, साठ-गाठ कर यह भ्रष्ट रिश्वतखोर सिकरवार थांदला खंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) के पद पर बैठ गया। जिसके बाद सीएससी के माध्यम से प्रत्येक कार्य के पैसे रिश्वत के रूप में लेने की बात सामने आती रही है। वहीं प्राइवेट स्कूलों के प्रतिवर्ष रिनिवल मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन होते हैं, लेकिन उसका सत्यापन बीआरसी द्वारा किया जाता है। सत्यापन के नाम पर बीआरसी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों से पृथक-पृथक राशि लेता था। यानी कि कोई प्रभावी स्कूल संचालक है तो वह रिश्वत के रूप में कम से कम 5 हजार रूपए सत्यापन करने हेतु दिया जाता था। उक्त 5 हजार रूपए देने वाला स्कूल संचालक की बात माने तो यह राशि खुशी से देना बताया जाता है। क्योंकि ऑफिसो में बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता है यह मान लिया गया है। वही जो प्रभावी स्कूल संचालक नहीं है उससे रिश्वत की राशि का तोल-मोल कर भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर संजय सिकरवार रिश्वत लेता था उसके बाद ही वह सत्यापन करता था। वहीं स्कूलों के निर्माण कार्य हो या फिर समूह द्वारा मध्यान भोजन का मामला हो संजय सिकरवार बिना लिए कुछ नहीं करता। कही कुछ बड़ा मामला हो भी जाए तो पैसा लेकर उसे निपटा दिया जाता था।

बतादे कि, थांदला ब्लॉक के ग्राम बेडावा में स्थित ज्ञान गंगा एकैडमी जो की 2018 से बेड़ावा में संचालित हो रही है। जिसका वार्षिक रिनीवल मान्यता हेतु स्कूल संचालक ने ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई। लेकिन सत्यापन करने हेतु बीआरसी संजय सिकरवार ने 18 हजार रुपए रिश्वत के मांगे और तोल-मोल कर 11 हजार में सत्यापन करने की हां संजय सिकरवार ने की। उक्त रिश्वत के 11 हजार रूपए संजय सिकरवार को देने हेतु बेडवा स्थित ज्ञान गंगा एकैडमी के संचालक बीआरसी कार्यालय पहुंचा। बीआरसी कार्यालय के आसपास पहले से ही घात लगाकर रिश्वतखोर संजय सिकरवार को पकड़ने हेतु इंदौर लोकायुक्त टीम घात लगाकर बैठी थी। जब स्कूल संचालक, संजय सिकरवार को रिश्वत देने कार्यालय के अंदर गया तो, शातिर रिश्वतखोर संजय सिकरवार ने पहले सीधे अपने हाथ में रिश्वत का रुपया नहीं लिया और कार्यालय के चपरासी श्यामलाल ने यह रुपया लिया और श्यामलाल ने उक्त रिश्वत का रुपया अपने अधिकारी उर्फ भ्रष्ट बीआरसी संजय सिकरवार को दे दिया। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने बीआरसी संजय सिकरवार व चपरासी श्यामलाल दोनों को रिश्वत लेते दर दबोचा और लोकायुक्त टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की। उक्त कार्यवाही के बाद भले ही विभाग एवं जिला प्रशासन की किरकिरी हुई हो लेकिन भ्रष्ट सिकरवार के चेहरे पर सिकन तक नहीं देखी गई और लोकायुक्त कार्यवाही के दौरान कुर्सी पर टेका लगाकर झूलता रहा। वहीं धान के साथ धनेरिये के रूप में पीसा गया चपरासी के चेहरे पर मायूसी देखी गई।

रिश्वत खौर सिकरवार की एक कारस्तानी माही की गूंज में 14 नवम्बर को प्रकाशित की थी। जिसपर प्रशासन कर देता कार्रवाई तो आज नही होती किरकिरी।

पूर्व में सिकरवार के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती तो नहीं होती प्रशासन की किरकिरी

बतादे कि, थांदला ब्लॉक के ग्राम रतनाली में 18 अक्टूबर 2024 को नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने शासकीय माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण बच्चों को मध्यान भोजन देते समय किया था। जिसमें अनियमितता सामने आने पर बीईओ थांदला को मय फोटो के साथ समूह एवं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु नायब तहसीलदार ने निर्देश दिए थे। बीईओ ने जाच करने हेतु बीआरसी को कहा और इस भ्रष्ट बीआरसी संजय सिकरवार ने प्राथमिक स्कूल के प्रभारी शिक्षक के हाथों समूह की ओर से एक आवेदन माफी नामा का लिखवा कर लिया। उक्त प्रतिवेदन में निरीक्षण दिनांक 18 अक्टूबर व 21 अक्टूबर दोनों दर्शाई गई। दो दिनांको के उल्लेख वाले उक्त प्रतिवेदन का रिश्वत लेकर गलत को सही होने का सत्यापन कर दिया और नायब तहसीलदार के निर्देशो की धज्जियां उड़ाकर मामले को रफा दफा कर दिया। माही की गूंज ने उक्त मामले को 14 नवंबर 2024 के अंक में बीआरसी संजय सिकरवार की तमाम करतूत को मयप्रूफ के साथ प्रकाशित किया था। जिसमे लिखा था कि, संजय सिकरवार ऑफिस में बैठकर क्षेत्र में अनियमितता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और अपनी जेब भर रहे हैं। गुंज ने यह भी उल्लेख किया था कि, बीआरसी संजय सिकरवार पर उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाना चाहिए और ऐसे जेब भरु व अपनी मनमानी के साथ लापरवाही करने वाले अधिकारी के विरुध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए लिखा था। जिसके बाद अगर जिला प्रशासन इस रिश्वतखोर संजय सिकरवार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती तो तय है कि, आज विभाग और जिला प्रशासन, लोकायुक्त कार्यवाही के बाद हुई किरकिरी से बच जाता।

रिश्वत की कार्यवाही के बाद भी निलंबन की कार्यवाही में देरी

सिकरवार की पकड़ कितनी मजबूत है और थी इस बात से ही पता चलता है कि, लोकायुक्त कार्यवाही के बाद बीआरसी की प्रतिनियुक्ति से हटाकर मूल विभाग में भेज दिया तथा बीईओ दीपेश सोलंकी को बीआरसी का प्रभार दिया गया। वही जनजाति कार्य विभाग ने संजय सिकरवार के निलंबन की कार्यवाही में देरी बरतने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी साठ-गाठ के आरोप सिकरवार के साथ होना चर्चा का विषय बना हुआ है।

नायब तहसीलदार के निरीक्षण व निर्देश की तोहीन, बीआरसी ने किया मामला गोल-मोल

मामला: रतनाली की माध्यमिक स्कूल में मेन्यु अनुसार भोजन नहीं बनने व नायब तहसीलदार के निरीक्षण का

रिश्वत खौर संजय सिकरवार लोकायुक्त कार्यवाही के दौरान कुर्सी टेका लेकर बेठा और झुलता रहा।

नशीले पदार्थ के नियंत्रण हेतु हुई बैठक

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मंगलवार को नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की बैठक ली गई। बैठक में नशे के आदि व्यक्तियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाए जाने के लिए जिले में नशीली दवाइयों, पदार्थों के सेवन से शारीरिक बीमारियों-दुष्प्रभावों के संबंध में जिले में व्यापक रूप से जन-जागरुकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये।

समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं का समय-समय पर चिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा स्कूल, कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को नशे में संलिप्तता की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की नियमित काउंसलिंग कर शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने को कहा गया। समस्त शालाओ के आस पास कही पर भी कोई मादक पदार्थ नहीं पाया जाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल द्वारा कहा गया कि, जिले में जिन-जिन स्थानों या शहर से बाहर स्थित आवासीय कॉलोनियों के आसपास कतिपय व्यक्तियों, नवयुवकों द्वारा नशीली दवाईयो का सेवन किए जाने की सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है तो ऐसे स्थानों का चिन्हांकन करे एवं नशे की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तत्काल अवगत कराए।

किसान अपने मोबाइल एप से कर सकता है पंजीयन

माही की गूंज, झाबुआ।

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसान गिरदावरी एप के सत्यापन के बगैर भी अपने मोबाईल निम्न प्रक्रिया अनुसार पंजीयन कर सकते हैं। ई-उपार्जन पोर्टल पर गूगल पर से लिंक पर क्लिक कर स्वयं भी कर सकते है।

निःशुल्क पंजीयन कृषक स्वयं किसान एप के माध्यम से, सहकारी समिति एवं विपणन संस्थाओ द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र से जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्र से तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर किया जा रहा है। तथा सशुल्क पंजीयन व्यवस्था निर्धारित शुल्क 50 रुपये एमपी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्रो पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में अग्नि एवं विस्फोट दुर्घटनाओं से बचाव तकनीक विषय पर एक दिवसीय जिला आपदा प्रबंधन क्षमता वृद्धि कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर नेहा मीना व पुलिस अधीक्षक पद्?म विलोचन शुक्ल ने दीप प्रज्वलन कर की। कार्यशाला में जिले के पुलिस, पंचायत, वन विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेंस एसडीईआरएफ, एनसीसी, एमएसएस, नेहरू युवा केन्द्र व जन अभियान परिषद के साथ नगरपालिका व नगरपरिषद झाबुआ, मेघनगर, थांदला, पेटलावद व राणापुर के फायरमैन सम्मिलित हुए।

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने अपने जिले में जिलास्तरीय फायर रीस्पान्स स्ट्राइक टीम पूरी तरह सक्रिय रहने का आव्हान किया ताकि किसी भी हादसे से लोगों की जान माल बचाने में सक्षम हो सके। प्रतिभागियों में कार्यशाला को काफी उपयोगी बताया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भास्कर गाचले द्वारा कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सर्टीफिकेट वितरित किए। गेल इंडिया लिमिटेड झाबुआ के सीनियर वरिष्ठ प्रबंधक श्री चौहान व उनकी टीम द्वारा गैस पाइप लाइन एवं पब्लिक सेफ्टी के बारे में बताया गया। तथा नगरपालिका के फायर ऑफिसर सुशील वाजपेयी ने रुरल फायर से निपटने की जानकारी दी।

घरेलू गैस के दुरुपयोग की आकस्मिक जांच

माही की गूंज, बडवानी।

ग्राम सिलावद में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग के संबंध में बुधवार को खाद्य विभाग के दल द्वारा जांच की गई । जांच के दौरान सिलावद के सुभाष पिता हरी के पास से 1 सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन, तुकाराम पिता गणपत, धनगर होटल, निर्मला बाई पिता काशीराम, जयश्री श्याम होटल, अनुराग पिता सुरेश पाटीदार, पाटीदार होटल से 1-1 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गंगाराम पिता सबकारिया, धीरज चिकन सेंटर से 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग करते पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3,7 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये हैं। बने प्रकरणों को आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित किये जायेंगे।

ग्रामीण विकास योजनाओं का लिया जायजा

माही की गूंज, खरगोन।

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 19 फरवरी को सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित भगवानपुरा विकासखण्ड के ग्राम सिरवेल पहुंचकर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष महेन्द्र सिंह किराड़े एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री बीएस आचाले सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर सुश्री मित्तल ने ग्राम सिरवेल की गलियों में भ्रमण कर नल जल योजना में किये गए कार्य एवं पाईप लाईन को देखा। ग्राम सिरवेल की नल जल योजना से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर जल कर की वसूली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत भवन में सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अपने समग्र आईडी को आधार नंबर से लिंक करा लें। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों एवं 70 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने कहा गया। किसानों से कहा गया कि वे अपनी फार्मर आईडी शीघ्र बनवा लें।

हाई स्किल्ड पेशेवर तैयार करने की चुनौती

यकीनन इस समय जहां नए डिजिटल दौर में देश की नई हाई स्किल्ड पीढ़ी के लिए भारत में ही नहीं, दुनियाभर में नए दौर की नौकरियों में अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं करोड़ों युवाओं को नए दौर की इन नौकरियों के लिए शिक्षित-प्रशिक्षित करने की बड़ी चुनौती भी सामने है। खासतौर से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह चुनौती और अधिक है।

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'भविष्य की नौकरियों' में कहा कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 17 करोड़ नई हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 9.2 करोड़ परंपरागत नौकरियां समाप्त होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 7.8 करोड़ अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी। तकनीकी उन्नति, जनसांख्यिकीय बदलाव, भू-आर्थिक तनाव और आर्थिक दबाव आदि परिवर्तनों के कारण नई हाई स्किल्ड नौकरियों को रफ्तार मिलेगी और इससे दुनियाभर में उद्योगों-व्यवसायों को नया रूप मिलता दिखाई देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत में नियोक्ताओं का मानना है कि सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उनके परिचालन में बदलाव आएगा, वहीं क्वांटम और एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भी परिचालन में परिवर्तन होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, विश्व स्तर पर एआई कौशल की मांग में तेजी आई है, जिसके क्षेत्र में भारत और अमेरिका अग्रणी नजर आते हैं। ऐसे में सबसे तेजी से बढ़ती जिन नौकरियों की भूमिकाएं होंगी, उनमें एआई, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा प्रबंधन के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये सभी नौकरियां वैश्विक रुझानों के साथ निकटता से जुड़ी हैं। इसी के चलते भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स वाले देशों में शामिल है। अगले दशक में भारत दुनिया की एक चौथाई नई हाई स्किल्ड वर्कफोर्स का हब भी बनता दिखाई दे सकता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि यद्यपि दुनिया में यह आशंका है कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां सृजित होती हैं। इसलिए हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को हाई स्किल्ड बनाते हुए नए काम के तरीकों के लिए उन्हें तैयार करने में निवेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए बहुत कम लागत पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। साथ ही इंडियाएआई मिशन प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

निःसंदेह, भारत की नई पीढ़ी डिजिटल दौर के हाई स्किल्ड कामों में लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन के मुताबिक एआई के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक, भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक, भारत की गणित में दक्ष नई पीढ़ी के लिए एआई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस समय जहां प्रतिभा संपन्न हाई-स्किल्ड नई पीढ़ी देश के विकास में बड़ा योगदान दे रही है, वहीं भारत के टैलेंट की दुनिया में पहचान है। भारत के प्रोफेशनल बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल स्तर पर अभूतपूर्व योगदान रहे हैं। ये हाई स्किल्ड पीढ़ी सेवा निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने वाली आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एआई सहित हाई स्किल्ड मैनपॉवर के आसान व किफायती रूप से उपलब्ध होने के कारण भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की तेजी से नई स्थापनाओं के साथ सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। जीसीसी जॉब मार्केट में नया चलन है। जीसीसी आईटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाल ही में नैसकॉम और जिनोव की और से जारी इंडिया जीसीसी लैंडस्केप रिपोर्ट के मुताबिक, जीसीसी के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता दिखाई दे रहा है।

कोई दो मत नहीं कि भारत देश -दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं की स्किल्स डेवलपमेंट व अपग्रेडेशन कर रहा है। महत्वपूर्ण यह कि इससे भारत के लिए हाई स्किल्ड सेवाओं के निर्यात की ऊंची संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेवा निर्यात के तहत कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल एआई, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग व मनोरंजन आदि से संबंधित सर्विसेज का एक्सपोर्ट शामिल है।

उल्लेखनीय है कि हालिया केंद्रीय बजट में देश के युवाओं को हाई स्किल्ड बनाने और भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। तीन नई कौशल विकास योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिनमें एआई के लिए 8800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इन योजनाओं के तहत खासतौर पर एआई, आईटी, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों में करीब 5 लाख युवाओं को हाई-टेक ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडिया एआई मिशन का एक मकसद एआई सहित हाई स्किल्ड मैनपॉवर के परिप्रेक्ष्य में देश-विदेश की मांग को पूरा करना है। यह मिशन भारत की युवा आबादी को देखते हुए महत्वपूर्ण है। बता दें कि यूरोप, जापान और अन्य कई विकसित और विकासशील देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। ऐसे में भारत के लिए विदेशों में भी अपने हाई स्किल्ड युवाओं के लिए बड़े अवसर हैं। भारत ने हाल के वर्षों में करीब दो दर्जन देशों के साथ आव्रजन और रोजगार से जुड़े समझौते किए हैं जिनके तहत भारत जापान, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, रूस, मॉरिशस, यूके, यूएई, रोमानिया और इटली जैसे देशों में अपने स्किल्ड युवा भेजे जाएंगे।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाई स्किल्ड टेलेंट की देश-दुनिया में लगातार मांग बढ़ रही है, ऐसे में हमें देश की नई पीढ़ी को हाई-स्किल्स डेवलपमेंट की विशेषज्ञता के लिए और अधिक तेजी से प्रवृत्त करना होगा। इस हेतु नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। देश के कोने-कोने में विशेषतया ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पायथन, वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ब्लॉक चेन और साइबर सुरक्षा जैसी हाई-स्किल्ड विधाओं में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाने के कई गुना प्रयास करने होंगे। उम्मीद करें कि नीति-नियंता भारत में नई पीढ़ी को नए उच्च डिजिटल गुणवत्ता वाले कौशल से सुसज्जित कर रोजगार देने व देश की आर्थिक तस्वीर संवारने के लिए कारगर रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे।

भक्ति करनी नहीं पड़ती है बल्कि होने लगती है- महामंडलेश्वर सेवानंद जी

माही की गूंज, आम्बुआ।

हम सनातनी हिन्दू है कुछ लोगों ने हमें भ्रमित कर दिया है इस कारण कुछ लोग अपना धर्म छोड़कर अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं हमें हमारा धर्म नहीं छोड़ना है। साधु संतों का संग करो वे हमें असुरी शक्तियों से बचाते हैं।

उक्त विचार आम्बुआ में आवास फलिया में नवनिर्मित त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग सहित शिव परिवार की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित सनातन सेवा आश्रम काछला के सदुरु महा मंडलेश्वर श्री सेवानंद जी गिरि महाराज ने धर्म सभा में व्यक्त करते हुए कहे। आगे आपने बताया कि, हमें दुष्टों का साथ छोड़ देना चाहिए, हमें व्यसनों को छोड़ देना चाहिए, साधु-संत लम्बी उम्र जीते हैं, जबकि व्यसनों में लिप्तों का जीवन छोटा होता है, हमें संतों के अनुभवों से सीख कर सत्य पर चलना चाहिए और असत्य का मार्ग छोड़ देना चाहिए, अंत समय में भक्ति ही साथ जाएगी भक्ति सदुरु से प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहें परमात्मा हमारे साथ रहता है।

धर्म सभा को देवास से पधारे पंडित श्री मुकेश तिवारी ने भी संबोधित किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी से सहयोग की अपील की। प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज से शुभारम्भ पूर्व बैंड-बाजों, ढोल मांदल की धुन पर कलश यात्रा शंकर मंदिर प्रांगण से निकाली गई जो कि कस्बे में घूमते हुए आवास फलिया में नवनिर्मित त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पहुंची। जहां पर विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान के विग्रहों को पूजन हेतु उचित स्थल पर विराजमान किया गया। यहां पर आगे के सभी विधि विधान पूर्ण किए जाने वाले हैं। शोभायात्रा में सनातन सेवा आश्रम काछला के सेवादार, संकटमोचन हनुमान मंदिर के पुजारी, श्री राम मंदिर आम्बुआ के पुजारी शंकर लाल पारिख तथा कस्बे के धर्म प्रेमी भक्तों एवं त्रिलोकेश्वर मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

सैंडविच में मिला कॉकरोच, रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई

माही की गूंज, उज्जैन।

नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ग्राहक को एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में अपने पनीर टिक्का सैंडविच के अंदर एक मरा हुआ कॉकरोच मिला। इस खोज के बाद आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मारा

रिपोर्ट्स के अनुसार, रवि बेदी नाम के एक व्यक्ति ने उज्जैन के सागर गैरे रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था। हालाँकि, खाते समय, वह अपने खाने में एक मरा हुआ कॉकरोच पाकर डर गया। बिना समय बर्बाद किए, उसने शहर के खाद्य विभाग को मामले की सूचना दी। उनकी शिकायत के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा और आगे की जांच के लिए दूषित सैंडविच को जब्त कर लिया।

मीडिया से बात करते हुए, रवि बेदी ने खुलासा किया कि यह पहली बार नहीं था जब सागर गैरे रेस्टोरेंट पर अस्वच्छ भोजन परोसने का आरोप लगाया गया था। कई ग्राहकों ने पहले भी खाने की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की थी, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह कोई अलग-थलग मामला नहीं है। हाल ही में, तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने राजेंद्रनगर के दो प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया और कई उल्लंघन पाए।

8 फरवरी को द फोर्ट में एक निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने चिकनाई और तेल टपकते हुए एग्जॉस्ट पंखे, अस्वच्छ रेफ्रिजरेटर और बिना लेबल के अनुचित तरीके से संग्रहीत उबली हुई सब्जियां पाईं। इसके अतिरिक्त, रसोई का फर्श अपर्याप्त जल निकासी के साथ गीला था, बर्तनों को ठीक से साफ नहीं किया गया था, और कॉकरोच का संक्रमण दिखाई दे रहा था। इसके अलावा, कीट नियंत्रण रिकॉर्ड गायब थे, और खाने का कचरा नियमित रूप से नहीं हटाया जा रहा था।

उसी दिन डेलिश बाय होम्स किचन में एक और निरीक्षण में इसी तरह के उल्लंघन सामने आए। रेस्टोरेंट समय पर खाने का कचरा निपटाने में विफल रहा, एग्जॉस्ट पंखे ग्रीस से ढके हुए थे, और खाद्य संचालकों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। अधिकारियों ने रसोई में पाव सहित बिना लेबल वाली कच्ची सामग्री भी खोजी। ये घटनाएं भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करती हैं।

नृत्य ईश्वर की साधना, इस साधना के लिए ओजस्वनी ने पांच साल तपस्या की

माही की गूंज, उज्जैन।

नृत्य ईश्वर की पूजा है। इस साधना के लिए ओजस्वनी ने पांच वर्षों तक तपस्या की। आत्मसत कथक मंगलवार को इस कला का बदला यह हुआ कि वह प्रशंसकों के लिए तरस गई। हजार सीटों वाले सूरसदन में उनका उत्साहवर्धन करने वाला एक भी प्रशंसक नहीं था। भारी मन से ओजस्वनी ने खाली सभागार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया।

मंगलवार को ताज महोत्सव का पहला दिन था। सूर सदन में शाम छह बजे से तीन प्रस्तुतियां होनी थीं, लेकिन आठ बजे तक न तो कलाकार आए और न ही प्रशंसक। जयपुर घराने के ओजस्वनी नृत्य प्रदर्शन के लिए बैठे रहे। रात साढ़े आठ बजे उन्होंने दुखी मन से सूरसदन ऑडिटोरियम के मंच पर कथक नृत्य के माध्यम से महाभारत नाटक का मंचन किया। ओजस्वनी घंटी की ध्वनि के साथ महाभारत धारावाहिक का गीत खाली सभागार में गूंज उठा। माता संयोगिता स्वयं एक नृत्यांगना थीं। उन्होंने कहा कि वह लखनऊ घराने के कलाकार हैं। पहली बार यह प्रदर्शन बिना किसी दर्शक के दिया गया। हर बार बेटी शिल्पग्राम में प्रस्तुति देती थी। इस बार उन्हें सूरसदन भेजा गया। यहां कोई दर्शक मौजूद नहीं है। कथक प्रदर्शन के बाद मंच की लाइटें बंद कर दी गईं।

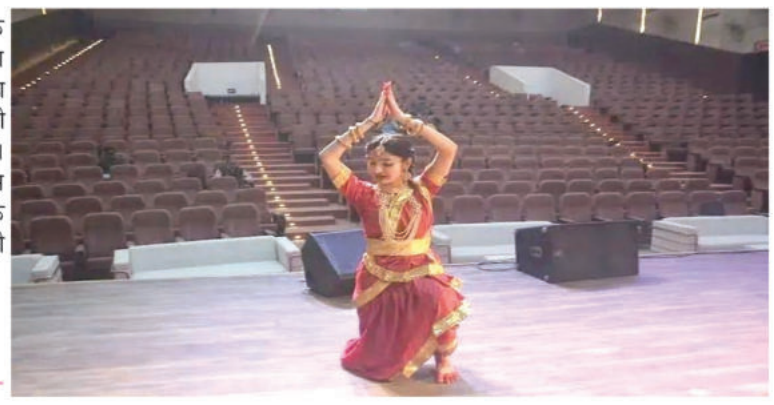

रंगमंच के कलाकार उज्जैन से नहीं आये थे

पहले दिन सूरसदन में उज्जैन के मिश्रित समाज संस्कृति संस्थान के रंगकर्मी सतीश डब्बा नाटक प्रस्तुत करने वाले थे। लेकिन, उनकी ट्रेन रद्द हो गई। वह रात 8.30 बजे तक सूरसदन नहीं पहुंच सके। शालिनी खरे को रामायण नृत्य प्रस्तुत करना था, लेकिन वह भी नहीं आईं।

अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया

एक ओर सूरसदन सभागार खाली रहा। दूसरी ओर शिल्पग्राम में उद्घाटन समारोह के पदाधिकारी व्यस्त दिखे। पर्यटन विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कारण सूरसदन में होने वाले कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार नहीं हो सका।

निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन

माही की गूंज, धार।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला अंधत्व निवारण समिति धार द्वारा जिले में 01 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक विशेष निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण एवं पहुँचविहीन क्षेत्रों में निर्धन और जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराना है। जिले में कुल 114 नेत्र परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिनमें से 16 फरवरी 2025 तक 78 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 1440 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित कर अनुबंधित अस्पतालों में भेजा गया है। अब तक 14528 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल इस अभियान के तहत 01 अप्रैल 2024 से 16 फरवरी 2025 तक 19850 मरीजों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 14528 मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। यह ऑपरेशन चोइथराम अस्पताल इंदौर, रेटिना स्पेशिलिटी अस्पताल इंदौर, अरबिंदो अस्पताल इंदौर, शंकर नेत्रालय इंदौर, जीवनज्योति अस्पताल मेघनगर, दृष्टि नेत्रालय दाहोद और जिला चिकित्सालय धार में विशेषज्ञ नेत्र सर्जनों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा, जिला चिकित्सालय धार में प्रतिदिन डॉ. सौरभ बोराशी एवं डॉ. गरिमा वैष्णव द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। निःशुल्क सुविधाएँ शिविरों में आए मरीजों को मुफ्त नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद ऑपरेशन, एम्बुलेंस/बस सेवा, ठहरने की सुविधा, भोजन, चश्मे और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक मोतियाबिंद मरीजों को इन शिविरों तक पहुँचाया जाए ताकि वे इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकें। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो भी मोतियाबिंद की समस्या से जूझ रहे हैं, वे नजदीकी शिविर में जाकर इस सुविधा का लाभ लें।

जिला अस्पताल में बन रहे मेडिकल कालेज के कार्य में लाए तेजी- कलेक्टर

माही की गूंज, उज्जैन।

जिला अस्पताल पसिर में आज सुबह यहां चल रहे मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने सीएनएचओ और सिविल सर्जन के साथ भवन डिसमेंटल के बाद किए जा रहे कामों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि, जिला अस्पताल परिसर में मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है इसके लिए 100 साल से अधिक पुराने जिला अस्पताल भवन को डिसमेंटल किया जा चुका है। यहां तोड़े गए भवन के मलवे को हटाकर समतलीकरण शुरु कर दिया गया है। इतना ही नही अस्पताल परिसर के बाहर आगर रोड़ पर तोड़-फोड़ के कारण कई दिनों से धूल उड़ रही है।

आज सुबह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल और सिविल सर्जन श्री निगम के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। धूल मुख्य सड़क पर न पहुंचे इसके इंतजाम करने के लिए भी उन्होंने ठेकेदार से कहा। साथ ही शेष रहे समतलीकरण के कार्य जल्द पूरा करने और प्रारंभिक निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए।

जनवरी में 83.84 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति कर संभाग में प्रथम

माही की गूंज, धार।

इंदौर संभाग के खनिज अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक आज संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संभागायुक्त ने खनिज राजस्व, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और कर निर्धारण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की गति तेज की जाए और तय समय सीमा में लक्ष्यों को पूरा किया जाए।

धार जिला रहा अव्वल

बैठक में बताया गया कि जनवरी माह में इंदौर संभाग ने कुल 147.675 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की, जिसमें धार जिला 83.84 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावाः झाबुआ दृ 8.33 करोड़ रुपये (द्वितीय स्थान), आलीराजपुर दृ 4.575 करोड़ रुपये (तृतीय स्थान) संभागायुक्त ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।

अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती

संभाग में अवैध उत्खनन के 127 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 92 प्रकरणों का निराकरण कर 87.823 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। अवैध परिवहन एवं भंडारण के 987 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 867 प्रकरणों का निराकरण कर 921.11 लाख रुपये की वसूली की गई। इन मामलों के निराकरण और जुर्माने की वसूली में धार जिला प्रथम स्थान पर रहा। खनन कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति संभागायुक्त ने बताया कि खनन से संबंधित 1042 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 50 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इसके अलावा, 826 कर निर्धारण मामलों में 62.35 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया। संयुक्त दल का गठन और कार्यवाही के निर्देश संभागायुक्त श्री सिंह ने खनिज एवं अन्य विभागों का संयुक्त दल गठित कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाए और नियमित निरीक्षण किया जाए। बैठक में संभाग के सभी जिलों के खनिज अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार कर लें - कलेक्टर

माही की गूंज, धार।

धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वच्छ पीथमपुर अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी, सहायक कलेक्टर वसीम अहमद बट, एसडीएम प्रमोद गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। पीथमपुर नहीं है क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया औद्योगिक प्रदूषण के व्यापक विश्लेषण के बावजूद पीथमपुर को क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार लगातार निगरानी रख रही है और इसे और अधिक स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त प्रयास बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एमपीआईडीसी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। गंदगी के स्रोतों की पहचान कर उनका प्रबंधन किया जाएगा। गैप एनालिसिस के आधार पर शोर, जल, वायु और प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्य प्रदूषण कारक और समाधान नाले में गंदे पानी का बहाव दृ घरेलू और औद्योगिक वेस्ट की पहचान कर इसे रोका जाएगा। धूल और प्लास्टिक कचरा दृ सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। शोर और वाहन प्रदूषण दृ कारण सड़कों को हो रहे नुकसान की जवाबदेही तय कर संबंधित विभागों से मरम्मत कराई जाएगी।औद्योगिक क्षेत्र को रहने योग्य बनाना दृ पर्यावरण सुधार के लिए उद्योगों को जागरूक किया जाएगा और ओरिएंटेशन

पुलिस, आरटीओ और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त प्रयास से कार्रवाई की जाएगी। सड़क क्षति दृ खदानों के मीटिंग आयोजित करेगा। तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को इस परियोजना में शामिल किया जाए। नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

एक्शन प्लान और निगरानी व्यवस्था

लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कार्य योजना तैयार की जाएगी। थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर पर्यावरण प्रदूषण का निष्पक्ष आकलन किया जाएगा। पहले नोटिस, फिर कार्रवाई दृ उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस देकर सुधार का समय दिया जाएगा, तत्पश्चात आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी दृ स्थानीय प्रशासन, उद्योग, मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को अभियान में जोड़ा जाएगा। पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पीथमपुर को एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे भविष्य में यहां बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कार्य किया जाएगा। स्वच्छ पीथमपुर अभियान के तहत सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करेंगे और समय-समय पर राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

आम्बुआ में प्रथम नेत्रदान हुआ, किसी का जीवन प्रकाशित होगा

माही की गूंज, आम्बुआ।

जीते जी रक्तदान मरने पर नेत्रदान की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु कस्बे के राठौड़ परिवार ने अपने प्रिय जन स्व श्री फूलचंद रामलाल राठौड़ के नेत्रदान कर किया। परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ जोबट को सूचित किया गया। जहां से नेत्र संग्रह टीम ने आम्बुआ आ कर स्व. फूलचंद राठौड़ के नेत्रों से कार्निया संग्रह कर नेत्र संग्रहालय इंदौर भेजा। आगामी दिनों में किसी जरूरतमंद को यह कार्निया प्रत्यारोपित किया जाकर जीवन में छाऐ अंधकार को मिटाकर जीवन को प्रकाशित किया जाएगा। जिन्हें रोशनी मिलेगी वह जब तक जीवित रहेगा तब तक स्व. फूलचंद राठौड़ भी अमर रहेंगे। वह परिवार अप्रत्क्ष रूप से ही सही इन का आभारी रहेगा। स्मरण रहे कि, आम्बुआ में शायद यह पहला नेत्रदान हुआ है, नेत्र संकलन केंद्र जोबट द्वारा दानकर्ता परिवार को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना एवं स्वर्गीय आत्मा को श्रृद्धांजलि अर्पित की गई।

यूरिया चोरी का खेल : रतलाम से मेघनगर के लिए निकला 80 टन यूरिया गायब, निजी गोदाम में हुआ खाली

माही की गूंज की खबर पर हुई कार्यवाही के बाद नवम्बर में मेघनगर की तीन उर्वरक ईकायों में भी मिला था बड़ी मात्रा में बिना बिल का सब्सिडी वाला यूरिया

माही की गूंज, मेघनगर।
इमरान शेख

रतलाम वेयर हाउस से मार्कफेड गोदाम के लिए 11 फरवरी को निकला 100 टन श्रीराम यूरिया में से सिर्फ 25 टन यूरिया ही 13 तारीख को मेघनगर मार्कफेड गोदाम में पहुंच पाया। बाकी रतलाम के श्री राम वेयर हाउस से बुधवार को अरिहंत ट्रांसपोर्ट के चार ट्रकों में निकला 1790 बैग यानी 80 टन यूरिया बीच में ही प्रज्ञा सेल्स के गोदाम में उतार कर गायब कर दिया गया था। जिसके बाद गाड़ियों का खराब होने का कारण बताया गया था। वैसे 80 और 25 कुल 105 टन होता है, मगर इसमें भी क्या बड़ा खेल हो सकता है उसका खुलासा भी हम कर रहे है।

उक्त प्रज्ञा सेल्स गोदाम के मालिक आशीष मांडोत को बताया जा रहा हैं। इस पूरी गड़बड़ी की जानकारी की सूचना जैसे ही गुरुवार को रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को मिली जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम अनिल भाना, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया द्वारा गोदाम में छापामार कर्यवाही कर यूरिया को जब्त किया गया।

कई सवाल गंभीर, सवाल जो सीधे यूरिया की चोरी की और इशारा करते हैं

पूरे घटनाक्रम में कई सवाल है जो लाखों रुपए के यूरिया की चोरी की और इशारा करते हैं। जैसे एक ही साथ चार ट्रक कैसे खराब हो सकते हैं...? ट्रक खराब हुए तो प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी...? ट्रक खराब हुए तो माल जिन ट्रकों में लोड कर प्रज्ञा सेल्स के गोदाम में पहुंचाया गया उन्हीं ट्रैकों से प्रशासन को ट्रक खराब होने की सूचना देकर पुरानी बिल्टी निरस्त कर नई बिल्टी से यूरिया को मेघनगर के विपणन के गोदाम में क्यों नहीं पहुंचाया गया...? कुल मिलाकर पूरा मामला संदिग्ध होकर सब्सिडी में मिलने वाले यूरिया का चोरी किया जाना ही प्रतीत होता है। इस पूरे खेल में रतलाम वेयर हाउस के अधिकारियों , ट्रांसपोटर, मेघनगर मार्कफेड गोदाम के प्रभारी और जिला अधिकारियों, स्थानीय और जिला कृषि अधिकारियों सहित सभी की भूमिका संदिग्ध ही नजर आ रही है...!

कुछ माह पूर्व नवंबर में भी मेघनगर की तीन उर्वरक इकाईयों में भी मिला था बड़ी मात्रा में यूरिया

माही की गूंज लगातार मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में कैल्शियम सल्फेट डायहाइड्रे (जिप्सम) से बनाए जा रहे नकली उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र सरकार की सब्सिडी की चोरी, टैक्स चोरी के समाचार प्रकाशित कर रहा है। जिसके बाद केंद्रीय उर्वरक विभाग के उड़नदस्ते ने मेघनगर की तीन उर्वरक इकाईयों मोनी मिनरल्स, त्रिम्भकेश्वर और बालाजी एग्रो पर छापामार कार्यवाही की गई थी। इस छापामार कार्यवाही में भी बड़ी मात्रा में इफको कंपनी सहित अन्य कम्पनियों का यूरिया जब्त किया था। मगर उक्त कार्यवाही में भी जिला कृषि विभाग के अधिकारियों ने मालिको को बचाने के लिए सारे आपराधिक प्रक्रिया के नियमों को ताक में रखकर मालिकों को आरोपी बनाए जाने की बजाए नौकरों के नाम के आवेदन थाने में दिए। वही ना ही जांच में पुलिस ने मालिकों को आरोपी बनाया, ना ही उक्त प्रकरण में किसी आरोपी को कानूनी प्रक्रिया अनुसार गिरफ्तार किया गया, न ही पूछताछ की गई। वरना उसी प्रकरण में पुलिस, आरोपियों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(1) में सूचना संकलित कर इन इकाईयों को यूरिया बेचने वाले विक्रेताओं और उन विक्रेताओ से जिन्होंने इन उर्वरक इकाईयों के मालिकों को यूरिया विक्रय किया है हिरासत में पूछताछ की जाती तो परत दर परत इस यूरिया चोरी के खेल में सम्मिलित सभी लोगों का खुलासा उसी प्रकरण में हो सकता था।

रतलाम प्रकरण में अभी तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई समझ से परे

रतलाम वेयर हाउस से निकले 80 मेट्रिक टन यूरिया को निजी गोदाम में खाली करवाने के प्रकरण में जिस त्वरित गति से रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने एक छोटी सी सूचना पर कार्यवाही करवाई। उसके लिए वह और इस पूरी कार्यवाही को अंजाम देने वाले उनके तीनों अधीनस्थ अधिकारी बधाई के पात्र है। मगर माही की गूंज को सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, पूरे घटनाक्रम के 6 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। जो काफी संदिग्ध प्रतीत होता है। जबकि पूरे घटनाक्रम की परिस्थितियों को देखा जाए तो इस मामले में उसी दिन अधिकृत ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 316(5), 318(4), 303(1) सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। जिससे की यूरिया चोरी के इस पूरे खेल का खुलासा हो सके।

कृषि विभाग की साठगांठ से मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में खुलेआम इकाईयां बना रही नकली उर्वरक

माही की गूंज पर लगी मोहर : औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय उर्वरक विभाग की छापामार कार्रवाई, 3 उर्वरक इकाइयों पर एफआईआर

नकली उर्वरक छापामारी में अधिकारियों का खेल: मालिकों को बचाने के लिए नौकरों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन

13 जून, 14 नवम्बर, 5 दिसम्बर 2024 के अंक में प्रकाशित समाचार।

कहीं पूरा खेल सबकी मिलीभगत से तो नहीं चल रहा है...!

किसानों को मिलने वाले सब्सिडी के इस यूरिया चोरी के खेल में कहीं ना कहीं वेयर हाउस संचालकों, ट्रांसपोर्टरों,

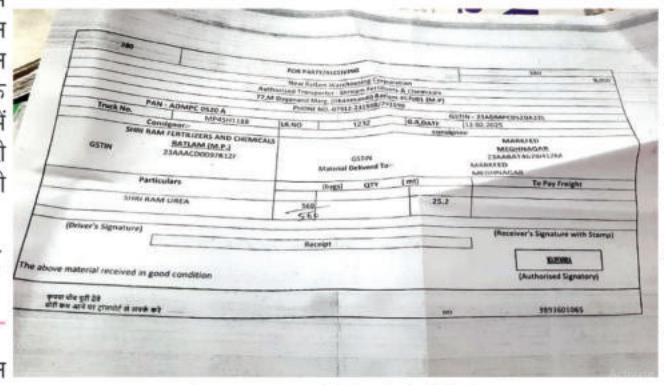
मेघनगर पहुचा 25 टन यूरिया जिसकी ट्रांसपोर्ट बिल्टी।

विपणन गोदाम के संचालकों, कृषि विभाग के अधिकारीयों सबकी मिलीभगत का अंदेशा दिखाई देता है। क्योंकि जब मेघनगर विपणन गोदाम के लिए आवंटन 100 टन का था। तो जब 80 टन माल रतलाम में पकड़ा गया तो फिर मेघनगर में 25 टन कैसे प्राप्त हो गया...? यह भी संदिग्ध ही है। क्योंकि 80 और 25 कुल 105 टन यूरिया होता है। तो कहीं रतलाम से यूरिया की भेजी जा रही विपणन के गोदाम की हर गाड़ी में यूरिया सिर्फ 20 टन भेजकर बिल्टी 25 टन की तो नहीं भेजी जा रही है...? जिससे प्रत्येक आने वाले ट्रक में 5 टन यूरिया रतलाम में ही होल्ड कर इकठ्ठा कर एक साथ कालाबाजारी कर बेच तो नहीं दिया जा रहा है...? और सरकारी यूरिया विक्रय केंद्रों पर उन्हें पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसान को एक बोरी विक्रय कर 2 बोरी विक्रय की बिलिंग दिखा कर रिकॉड को मेंटेन तो नहीं कर दिया जा रहा...? आदी उक्त खडे हो रहे सवालो को तर्कविहीन नही कहा जा सकता।

पॉइंट ऑफ सेल मशीन से निकलने वाली पर्ची नहीं देते किसानों को

मेघनगर मार्कफेड गोदाम से किसानों को खाद विक्रय करते वक्त ना तो बिल की प्रति प्रदाय की जाती है जो संदिग्ध है। साथ ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन से वितरण उपरांत निकलने वाली पर्ची को भी रिकॉर्ड में स्टोर नहीं रखा जाता। फिर ये कैसे क्रॉस चेक होगा कि, वास्तव में किस किसान को कितना बोरी खाद आवंटित किया गया, जो संदिग्ध है। और ये हमारी इस बात को भी पुख्ता करता है कि, कही अंगूठा लगाकर कम बोरी देकर रिकॉर्ड में किसान को ज्यादा यूरिया विक्रय बताकर खेल तो नहीं किया जा रहा...? और इस अतिरिक्त विक्रय की आड़ लेकर रिकॉड को मेंटेन करते हुए वह केंद्र सरकार का सब्सिडी का यूरिया निजी दुकानदारों और नकली उर्वरक इकाईयों को तो नहीं बेच दिया जा रहा है...? ऐसे में क्या करोड़ों की सब्सिडी वाले यूरिया को बेचकर केंद्र सरकार को चुना लगाया जा रहा है...!

यूरिया के इस खेल की परतों को खोलने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत

रतलाम और झाबुआ दोनों जिलों में सब्सिडी की यूरिया चोरी के आर्थिक अपराध का यह खेल कितना व्यापक है और इस पूरे खेल को कौन-कौन सरकारी और निजी गिरोह की टीम के खिलाड़ी मिलकर खेल रहें है। ये तभी साफ हो पाएगा जब इस पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम को छापामार कार्रवाई कर फाइलों को जब्त करे। तथा विस्तृत जांच शुरू करनी चाहिए। साथ ही ये भी जांच करनी चाहिए कि, मेघनगर आद्योगिक क्षेत्र में चल रहें नकली उर्वरक बनाने और उस नकली उर्वरक की आड़ में भी केंद्र सरकार से सब्सिडी लेकर सरकार को अरबों का चुना लगाने के लिए कौन से उर्वरक उद्योग लगा रहें है। उन सबको भी जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि, यही प्रति वर्ष मरने वाले 6 हजार से ज्यादा किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके बच्चों और परिवारों के लिए सही न्याय होगा।

फ़ोटो शेसन के चक्कर मे पुलिस ने परीक्षा के पूर्व बच्चों पर डाला अतिरिक्त दबाव

स्कूल प्रशासन की लापरवाही, खामियाजा भुगतना पड़ा स्कूली बच्चों और परिजनों को

पुलिसिया कार्रवाई से स्कूल प्रशासन आखिर क्यों रहा वंचित

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के चलते हर वर्ग के लोगो मे रील का ट्रेंड देखा जा रहा है। जिससे स्कूली बच्चे भी वंचित नही है। आये दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसा भी कर गुजरते है जो नीति गत नही होते और उसका सामाजिक प्रभाव भी अच्छा नही रहता। वर्तमान में कक्षा 10 वी और 12 की परीक्षा नजदीक है और उसके चलते स्कूलों ने फेरवेल पार्टी का दौर चल रहा है। जो फिलहाल अलग-अलग तरीको से आयोजित किये जाने के ट्रेड में है। खास कर निजी स्कूलों में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे जहा नियमो को ताक में रखकर सार्वजनिक रूप से आयोजन किये जा रहे है। जो स्कूल प्रशासन और स्कूली बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों के लिए भी परेशानी का सबब बन हुए है।

सफलता स्कूल के बच्चों को भारी पड़ा फेरवेल पार्टी का आयोजन

नगर की निजी स्कूल सफलता विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा विगत दिनों फेरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। जिंसमे कक्षा 11वी और 12वी के बच्चे शमिल हुए। पूरा आयोजन स्कूल परिसर में पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा था, लेकिन स्कूली बच्चों के जोश व जुनून या यूं कहें कि स्कूल प्रशासन का बच्चों पर नियंत्रण नही होना। एक ऐसे घटनाक्रम के रूप में सामने आया जिससे स्कूली नाबालिग बच्चे, स्कूल प्रशासन और बच्चों के परिजन सब सवालों के घेरे में आकर चर्चा का विषय बन गए। फेरवेल पार्टी के दौरान स्कूल के बच्चों ने एक वाहन रैली का आयोजन किया। जिंसमे फेरवेल पार्टी में शामिल बच्चे अपना निजी, किसी परिचित का चार पहिया वाहन लेकर पहुँचे ओर रायपुरिया रोड स्थित मंडी परिसर से स्कूल तक वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में कार, जीप के साथ एक जेसीबी मशीन भी शामिल थी। जिसके बकेड में स्कूल की कुछ लड़कियां सवार होकर नगर भृमण करती हुई स्कूल परिसर तक पहुँची। बात किसी के समझ में नही आई कि, क्या हो रहा है लेकिन रील ओर सोशल अकाउंट के दौर में खुद को ट्रेंडिंग में लाने के लिए ऐसा किया। बात सोशल मीडिया की थी तो जल्द ही पुलिस तक भी पहुँच गई और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ा और फिर जो हुआ वो नगर में नही बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस ने की चालानी कार्यवाही

इस मामले की जानकारी मिलने पर पेटलावद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जुलुस मे निकले वाहनों के मालिक व बच्चों के माता पिता को पुलिस थाने बुलाकर वाहनों के खिलाफ यातायात के नियमों के अनुसार चालानी कार्यवाही कर 5 हजार से लेकर 10 हजार तक के चालान वाहन मालिकों मतलब बच्चों के परिजनों के फाड़े। इस दौरान स्कूली बच्चे और उनके परिजन घण्टो पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे। पुलिस ने चालानी कार्यवाही के साथ-साथ बकायदा बच्चों के परिजनों को इस हरकत के लिए सार्वजनिक रुप से फुल की हार-माला पहनाकर उनके बच्चों द्वारा की गई हरकत के लिए सामाजिक रुप से शर्मिंदा कर जिला पुलिस के सोशल अकाउंड पर वीडियो जारी किए। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस की गांधी गीरी बताया गया।

इस संबध मे नगर निरीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि, इस प्रकार बच्चो के द्वारा निकाला गया जान जोखिम में डालकर किया गया कार्य व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से गलत है। जिसकी सूचना मिलते ही, वाहन मालिकों तथा अभिभावकों को पुष्पहार अर्पित कर, नियमानुसार कार्यवाही की गई और सभी को समझाइश दी गई।

परीक्षा से ठीक पहले हुई कार्यवाही का बच्चों पर कितना असर

स्कूल संचालक के माध्यम से स्कूली बच्चों द्वारा किया गया कृत्य कत्तई स्वीकार्य नही है और इस पर कानूनी कार्यवाही होना भी लाजमी थी। लेकिन इन सब के बीच स्कूली बच्चों की मुख्य परीक्षा जो कि बिल्कुल निकट है ओर परीक्षा के पूर्व फेरवेल पार्टी जैसे आयोजन बच्चों पर पढ़ाई के दबाव को कम करने और उत्साह और जोश के साथ परीक्षा में उतरने के लिए किए जाते है, पर यहां उल्टा हो गया। जिन बच्चों को परीक्षा में जोश से उतरना था वो उनकी वजह से हुई पारिवारिक फजीहत के चलते शायद उस जोश के साथ नही उतर कर निराशा के साथ जाने पर मजबूर होंगे। क्योकि इस आयोजन में शामिल ज्यादातर बच्चे मध्यमवर्गीय परिवार के है जिनके लिए पैसा नही प्रतिष्ठा ज्यादा मायने रखती है। इस पूरे मामले में जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आने के लिए गलती बच्चों ने की शायद वही गलती पुलिस भी दोहराते हुए पूरे मामले में बच्चों के परिजनों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर किया। जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक

सफलता विद्या मंदिर के बच्चों ने किया आयोजन।

बच्चों के मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

स्कूल प्रशासन आखिर कार्रवाई से अछूता क्यो...?

यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि, जहा एक ओर वाहन मालिकों पर हजारों रुपयों की चालानी कार्यवाही की गई और उनका फूल मालाओं से सार्वजनिक स्वागत (अपमान) किया गया। वही सफलता विद्या मंदिर स्कूल प्रशासन पर किसी प्रकार की कार्रवाई न तो पुलिस द्वारा की गई ना ही शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई की जानकारी सामने आई। मतलब साफ है कि, इतने बड़े आयोजन के पीछे जिंसमे नाबालिग बच्चे शामिल थे उसमें पुलिस और शिक्षा विभाग ने ये माना कि, इसमें स्कूल प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नही था।

बताया जा रहा है, स्कूल प्रशासन ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए इस आयोजन से खुद को अलग कर दिया और पूरे आयोजन को फेरवल पार्टी में जुटे बच्चों के मत्थे डाल दिया। इस आयोजन के बारे में कोई जानकारी नही होने और आयोजन वाले दिन सरकारी छुट्टी होने का हवाला देकर बच गए। जबकि पूरा आयोजन स्कूल परिसर में आयोजित हुआ बल्कि स्कूल स्टाफ भी आयोजन में शामिल था। बच्चों द्वारा

मंच की व्यवस्था संभालता स्कूल स्टॉफ।

क्रं. 19 स्कूल परिसर में आयोजित आयोजन का मंच जिंसमे फेरवेल पार्टी 2025 उलेखित है।

लाये गए वाहन भी स्कूली शिक्षकों की जानकारी में थे, इतना ही नही एक स्कूली शिक्षक भी वाहन की इस रैली में मौजूद था। सम्भव है रैली की जानकारी भी स्टाफ के पास पहुँची होगी जिसे वक्त रहते समझाइश के साथ न तो रोका गया न ही यातायात नियमों के साथ सीमित किया गया। स्कूल प्रबंधन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नही होना बड़े सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही पुलिसिया कार्यवाही पर सवाल उठ रहे है। जहां चालान की रसीद ओर वसूली गई राशि के आंकड़े में भी अंतर की चर्चा है। बच्चों और परिजनों को यातायात ओर सुरक्षा का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस कही न कही देश के भविष्य को नादानी में भ्रष्टाचार और अव्यवहार का पाठ पढ़ा गई।

स्कूलों में बढ़ते कॉम्पिटिशन के चलते हुआ पूरा मामला

ऐसा नही की केवल सफलता स्कूल के बच्चों ने ऐसा किया, नगर की अन्य निजी स्कूलों में भी फेरवेल पार्टी आयोजित हुई, लेकिन कई स्कूलों के आयोजन स्कूल परिसर में समाप्त हुए। तो कुछ के आयोजन इस तरह चर्चा में नही आये। तो कुछ स्कूलों ने इस घटनाक्रम के बाद अपने आयोजन को सीमित कर दिए। नगर में निजी स्कूलों के बीच अलग-अलग प्लेटफार्म पर कॉम्पिटिशन चल रहे है, उसमें से सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी है जहां अपनी स्कूल के आयोजन सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ा कर प्रचारित कर नये बच्चों को एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करते है। नगर में एक अन्य स्कूल के बच्चों के द्वारा भी फेरवेल पार्टी में वाहन रैली का आयोजन किया गया जो कि नगर के बहार-बहार निपटने के चलते चर्चा में नही आया। लेकिन इसी आयोजन से प्रेरित होकर सफलता स्कूल के बच्चों ने अति उत्साह में आकर इस प्रकार का आयोजन कर दिया जो कही न कही परेशानी का सबब बन गया।

बच्चों के आयोजन का समर्थन नहीं करता गूंज....

स्कूली नाबालिग बच्चों द्वारा किए गए इस प्रकार के आयोजन का कतई माही की गूंज समर्थन नही करता है और इस प्रकार के आयोजन पर स्कूल प्रशासन द्वारा समय रहते रोकने के पक्ष में है। स्कूली बच्चों की नादानी ओर स्कूल प्रशासन की लापरवाही किसी बच्चे की जान का कारण बन सकती थी जो नगर के लिए एक कलंक की तरह हो सकता था। गूंज, पुलिस कार्यवाही को भी दोषी नही मानती क्योंकि इस प्रकार के आयोजन से होने वाली किसी भी हानि का ठीकरा पुलिस के माथे फूटता है। नाबालिक बच्चों को वाहन देने वाले परिजनों पर चालानी कार्यवाही भी जायज थी। बच्चों के परिजनों को सबक लेना चाहिए कि, जब तक इस प्रकार के आयोजन स्पष्ट न हो और स्कूल प्रशासन खुद इसकी जवाबदेही न ले तब तक बच्चों को बड़े वाहन नुमाइश के लिए न दे। लेकिन स्कूल प्रशासन को इस कार्रवाई से वंचित रखा गया और बच्चों के परिजनों को ठीक परीक्षा के पूर्व समाज को संदेश देने के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना कतई उचित नही था। पुलिस इस प्रकरण को बच्चों के परिजनों को थाना परिसर तक सीमित कर प्रेस नोट के माध्यम से वाह-वाही लूट सकती थी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422